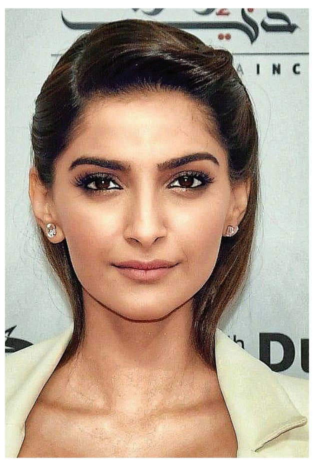

खबर जो सच उगले...

प्रचण्ड समय

हिंदी दैनिक समाचार पत्र

वर्ष-7, अंक-113, पृष्ठ-8, मूल्य- 1 रुपया

आरएनआई नंबर- एचपीएचआईएन/2019/79889

संपादक - अश्वनी वर्मा

70180-86211

prachandsamay.com

हिमाचल का सबसे तेज बढ़ता अखबार

सुविचार

जीवन को सुंदर बनाने के लिए जरूरी है कि हम अच्छे विचार रखें, अच्छे कर्म करें और हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखें।

दूसरी बार मां बनीं सोनम; बेटे को दिया... पेज-8

एपीजी शिमला विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति... पेज-6

शिमला, मंगलवार, 31 मार्च, 2026

हिमाचल विधानसभा से वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 58,830 करोड़ रुपये का बजट पारित

अश्वनी वर्मा . शिमला

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026–27 के लिए 58,830 करोड़ रुपये से अधिक का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सदन में पेश हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 के पारित होने के साथ ही राज्य सरकार को इस राशि को खर्च करने की वैधानिक अनुमति मिल गई है। मुख्यमंत्री ने इससे पहले 21 मार्च को अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया था, जिसका प्रारंभिक आकार 54,928 करोड़ रुपये था, लेकिन अब संशोधित रूप में इसे बढ़ाकर 58,830 करोड़ 66 लाख 70 हजार रुपये कर दिया गया है।

सरकार के इस बजट में स्पष्ट संकेत है कि राज्य की बड़ी राशि अनिवार्य खर्चों पर जाएगी, जबकि विकास कार्यों के लिए सीमित संसाधन उपलब्ध रहेंगे। बजट दस्तावेजों के अनुसार अगले वित्त वर्ष में सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले हर 100 रुपये में से लगभग 20 रुपये ही विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 27 रुपये वेतन, 21 रुपये पेंशन, 13 रुपये ब्याज अदायगी, 9 रुपये ऋण अदायगी और 10 रुपये स्वायत्त संस्थानों को अनुदान के रूप में खर्च किए जाएंगे।

राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार ने बजट में राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच अंतर को भी स्वीकार किया है। वित्त वर्ष 2026–27 में राज्य की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 40,361 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि राजस्व व्यय 46,938 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। इस तरह 6,577 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुमानित है। इसी तरह 9,698 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान लगाया गया है, जो प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.49 प्रतिशत है।

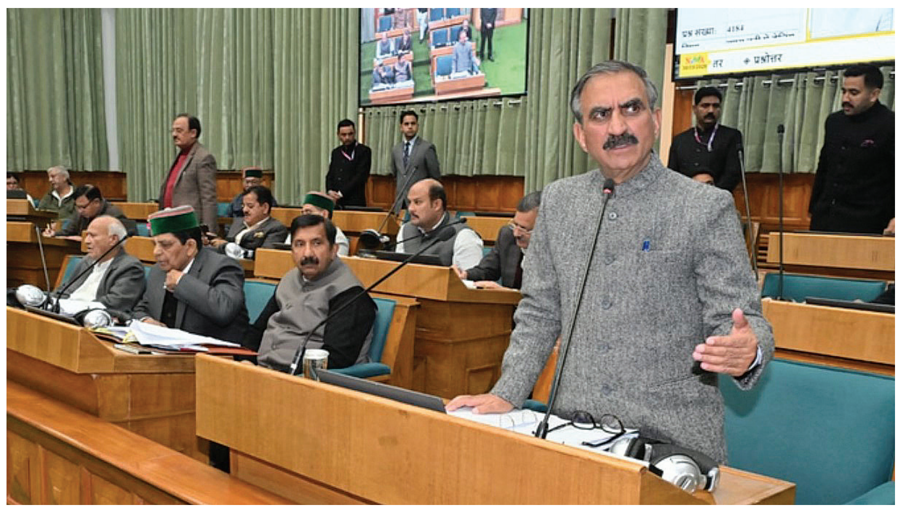

कमजोर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा निर्णय लेते हुए अपने वेतन का 50 प्रतिशत छह महीने के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों का 30 प्रतिशत तथा विधायकों का 20 प्रतिशत वेतन भी छह महीने के लिए स्थगित रहेगा। इसी अवधि के लिए निगमों और बोर्डों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, सलाहकारों और ओएसडी का 20 प्रतिशत वेतन भी रोका जाएगा।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिवों का 30 प्रतिशत वेतन स्थगित रहेगा, जबकि सचिवों से लेकर विभागाध्यक्ष स्तर तक के अधिकारियों का 20 प्रतिशत वेतन छह महीने के लिए रोका जाएगा। पुलिस विभाग में डीजीपी और अतिरिक्त डीजीपी का 30 प्रतिशत तथा आईजी से एसपी स्तर तक के अधिकारियों का 20 प्रतिशत वेतन स्थगित रहेगा। वन विभाग में भी पीसीसीएफ और अतिरिक्त पीसीसीएफ का 30 प्रतिशत तथा सीसीएफ से डीएफओ स्तर तक के अधिकारियों का 20 प्रतिशत वेतन स्थगित रहेगा। हालांकि ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों के वेतन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अस्थायी व्यवस्था है और आर्थिक स्थिति सुधरने पर यह राशि वापस कर दी जाएगी।

सरकार ने आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सामाजिक सुरक्षा और रोजगार से जुड़ी कई घोषणाएं भी बजट में शामिल की हैं। पुलिस विभाग में एक हजार कांस्टेबलों की भर्ती करने और अन्य रिक्त पदों को भरने की योजना है। इसके अलावा वर्ष 2016 से दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का भुगतान करने तथा 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारों को पेंशन एरियर देने की घोषणा भी की गई है।

पैरा कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकार ने आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सिलाई शिक्षिकाओं, मिड-डे मील वर्करों, राजस्व चौकीदारों, लंबरदारों, एसएमसी और आईटी शिक्षकों, एसपीओ तथा पार्ट-टाइम मल्टी टास्क वर्करों सहित कई श्रेणियों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सात वर्ष की सेवा पूरी कर चुके 823 कर्मचारियों के वेतन में औसतन करीब 14 हजार रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की घोषणा भी बजट का प्रमुख हिस्सा रही है।

बजट में सामाजिक कल्याण योजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने एक लाख अति गरीब परिवारों की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि के तहत 1,500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है। इसके अलावा 27 हजार गरीब परिवारों को कच्चे घरों की जगह पक्के मकान उपलब्ध कराने की योजना भी शामिल की गई है। दिव्यांग पेंशन को 1,700 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है और अन्य कई श्रेणियों की पेंशन में भी वृद्धि की गई है।

प्रचण्ड समय

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए भी सरकार ने कई कदमों का ऐलान किया है। अगले वित्त वर्ष में प्रदेश में 150 नए सीबीएसई स्कूल खोलने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा प्रदेश में नई टाउनशिप विकसित करने की योजना भी बजट में शामिल है, जिनमें हिम-चंडीगढ़, हिम-पंचकूला और कांगड़ा में धौलाधार की तलहटी क्षेत्र शामिल हैं।

इसके साथ ही सरकार ने 11 नई योजनाओं की घोषणा भी की है, जिनमें मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना, साइबर मित्र योजना, शुभ विवाह योजना, मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना और खेलो हिमाचल–चिट्टा मुक्त अभियान जैसी योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देने की कोशिश इस बजट में की गई है।

विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां के साथ उनके कार्यालय कक्ष में आज सदन की कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व शिष्टाचार भेंट करती बी0 डी0 सी0 चेयरमैन पांगी आशा किरण तथा अन्य पंचायत समिति सदस्य।

बजट सत्र (चरण दो) के 10वें दिन की कार्यवाही का संचालन करने सदन की ओर जाते हि0प्र0 विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां।

बजट सत्र (चरण दो) के 10वें दिन की कार्यवाही का सदन के अंदर संचालन करते हि0प्र0 विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां।

बजट सत्र (चरण दो) के 10वें दिन की कार्यवाही का संचालन करने विधान सभा सचिवालय पहुँचने पर गेट नं0 1 पर सलामी लेते हि0प्र0 विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां

मुख्यमंत्री नादानी से बाज आएं और बॉर्डर एरिया में हालात खराब होने से रोकें : जयराम ठाकुर

प्रचण्ड समय . शिमला

प्रदेश में एंट्री टैक्स को लेकर बढ़ रहे विवाद और बवाल पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बीते कल जिस प्रकार के हालात बने, वह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति किसी के लिए भी ठीक नहीं है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के लोगों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। खासतौर पर बॉर्डर एरिया में हिमाचल और अन्य प्रदेशों के लोग विरोध कर रहे हैं। बीते कल ढाई घंटे से अधिक समय तक प्रदर्शन चलता रहा और करीब 4 घंटे तक पूरा हाईवे जाम रहा। प्रदर्शनकारियों ने आज से हालात और बिगड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया है।

प्रचण्ड समय

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बिना सोचे-समझे लिए गए फैसलों के कारण ही ऐसी स्थिति बनी है। इसलिए मुख्यमंत्री को पूरे मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसका सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना चाहिए।

जयराम ठाकुर ने कहा कि टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोग भी एंट्री टैक्स का विरोध कर रहे हैं। टैक्सी यूनियन भी इसके खिलाफ है। इसके अलावा पंजाब के लोगों ने भी विरोध जताया है और कहा है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो हिमाचल में पंजाब से लगने वाले सभी एंट्री प्वाइंट्स पर हिमाचल के वाहनों को रोका जाएगा। इससे एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है और आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह कानून-व्यवस्था के लिए भी चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि छोटी गाड़ियों के शुल्क में अधिक वृद्धि नहीं हुई है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। छोटे वाहनों की एंट्री फीस में लगभग 234 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पहले हिमाचल प्रदेश के यूटिलिटी वाहनों को छूट थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। इसका सीधा असर किसानों, बागवानों और सब्जी उत्पादकों पर पड़ेगा।

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को तुरंत पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए और संवाद के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। सरकार के मनमाने फैसलों के कारण हिमाचल और पंजाब के बीच जो हालात बन रहे हैं, वे कतई उचित नहीं हैं। इस प्रकार की जिद दोनों राज्यों के बीच तनाव को बढ़ाएगी, जिसका खामियाजा प्रदेश की आम जनता को भुगतना पड़ेगा।

प्रचण्ड समय

अब रोजाना देखें प्रचण्ड समय का

ई-पेपर

www.prachandsamay.com

हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पाठकों का पसंदीदा अखबार

न्यूज ब्रीफ..

कोटखाई में चिट्टे के साथ दो गिरफ्तार, पिस्टल भी बरामद

अश्वनी वर्मा, शिमला . नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस ने शिमला जिला के कोटखाई क्षेत्र में चिट्टा बेचने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चिट्टा के साथ एक पिस्टल, चाकू और अन्य सामान भी बरामद किया गया है।

पुलिस के अनुसार रविवार शाम थाना कोटखाई के तहत कोकुनला के पास काले रंग की टाटा सफारी गाड़ी में सवार दो लोग चिट्टा बेचते हुए पकड़े गए।

आरोपियों की पहचान रमन जीत (50 वर्ष), निवासी मोहाली (पंजाब) और रूबेल (26 वर्ष), निवासी गांव ताकरोट डाकघर बगैर कोटखाई के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2.25 ग्राम चिट्टा, एक पिस्टल, एक छोटा चाकू और दो अतिरिक्त गैस सिलेंडर बरामद किए हैं।

इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी नशे की सप्लाई कहां से ला रहे थे और किन लोगों तक पहुंचा रहे थे।

इसी बीच शिमला जिले के ही चौपाल क्षेत्र में पुलिस ने एक अन्य कार्रवाई में एक व्यक्ति को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक थाना चौपाल के तहत चंबी क्षेत्र के ननाहर मोड़ के पास पुलिस टीम ने नरेंद्र सिंह उर्फ भूरा (46 वर्ष), निवासी गांव गागना डाकघर चंबी तहसील चौपाल को 90 ग्राम चरस के साथ पकड़ा है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों मामलों में आगे की जांच शुरू कर दी है और नशे के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं भविष्य के विकास का आधार - संजय अवस्थी

प्रचण्ड समय . सोलन

अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं भविष्य के विकास का आधार बनेगी। संजय अवस्थी गत दिवस अर्की विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सूरजपुर में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तहत 7.06 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले घनागुघाट से कुन्नी छिब्बर पिपलूघाट मार्ग के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने इस अवसर पर पिपलूघाट में 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले आजीविका भवन की आधारशिला भी रखी।

संजय अवस्थी ने कहा कि विकास की गति को आगे बढ़ाने में सड़कें अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ सड़क नेटवर्क लोगों की सुगम आवाजाही व व्यापार बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित बना रही है कि प्रदेश के प्रत्येक गांव तक बेहतर सड़क सुविधा पहुंचाई जाए।

विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों, बागवानों व पशुपालकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती से उगाए जाने वाली गेहूं, मक्की, अदरक व हल्दी की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में आशातीत बढ़ौतरी की गई है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो। उन्होंने कहा कि पशुपालकों की आर्थिकी को और सुदृढ़ बनाने के लिए गाय व भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी बढ़ाया गया है।

संजय अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश के कमज़ोर वर्गों तक विकास को पहुंचाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना कमज़ोर वर्ग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत बेसहारा बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक उनके पालन-पोषण के अतिरिक्त प्रति माह जेब खर्च भी दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य बेसहारा बच्चों को सम्मानजनक जीवन और उज्जवल भविष्य प्रदान करना है।

विधायक ने महिला मण्डल सीमू, महिला मण्डल भलेड़, महिला मण्डल सूरजपुर व युवक मण्डल सूरजपुर को 21-21 हजार रुपए देने की घोषणा की।

उन्होंने इस अवसर पर 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी और इनके शीघ्र निपटारे के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश कश्यप, उपभोक्ता मामले एवं विपणन महासंघ सोलन के अध्यक्ष सुरेन्द्र ठाकुर, जल शक्ति विभाग अर्की के अधिशाषी अभियंता विवेक कटोच, लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता के.के. चौहान, विद्युत बोर्ड के अधिशाषी अभियंता संदीप कुमार, खंड चिकित्सा अधिकारी अर्की डॉ. मुक्ता रस्तोगी, ग्राम पंचायत सूरजपुर के पूर्व उप प्रधान कामेश्वर ठाकुर व धनी राम ठाकुर, ग्राम पंचायत घनागुघाट के पूर्व उप प्रधान प्रवीण ठाकुर, ग्राम पंचायत दावंटी के पूर्व उप प्रधान हीरा सिंह कौंडल, महिला मण्डल सिम्मू की प्रधान प्रवीणा शर्मा, महिला मण्डल भलेड़ की प्रधान हीरा देवी, स्वयं सहायता समूह सूरजपुर की प्रधान राधा देवी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व ग्रामीण उपस्थित थे।

एंट्री टैक्स नया नहीं, सिर्फ बढ़ोतरी हुई, सरकार करेगी रैशनलाइजेशन: मुख्यमंत्री सुक्खू

अश्वनी वर्मा . शिमला

पंजाब के साथ एंट्री टैक्स को लेकर उठे विवाद के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने कोई नया एंट्री टैक्स लागू नहीं किया है बल्कि पहले से लागू व्यवस्था में सीमित बढ़ोतरी की गई है, जिसे जल्द ही रैशनलाइज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एंट्री टैक्स पिछले लगभग 30 वर्षों से लागू है और हालिया बढ़ोतरी मुख्य रूप से नेशनल हाईवे पर फास्टैग प्रणाली से इसे जोड़ने के कारण हुई है। मुख्यमंत्री के अनुसार इससे छोटी गाड़ियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है, जबकि बड़ी गाड़ियों पर करीब 40 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है, साथ ही 5 किलोमीटर के दायरे में छूट देने का प्रावधान भी किया जाएगा जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। इससे पहले, प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि इस फैसले के कारण पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ तनाव की स्थिति बन रही है और वहां के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के वित्त मंत्री की ओर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जिससे दोनों राज्यों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और हिमाचल के लोगों को दूसरे राज्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार से बातचीत कर समाधान निकालें, क्योंकि इसका व्यापक असर टैक्सी यूनियनों और आम लोगों पर पड़ रहा है। इस मुद्दे पर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने भी चिंता जताते हुए कहा कि सरकार को रैशनलाइजेशन से पहले ठेकेदारों और संबंधित पक्षों को विश्वास में लेना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सीमा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कुछ स्थानों पर सीमा बंद करने की चेतावनी भी दी गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने दोहराया कि एंट्री टैक्स कोई नई व्यवस्था नहीं है और इसका असर छोटी गाड़ियों पर नहीं पड़ेगा।

सिल्ट और ड्रेजिंग पर सरकार गंभीर, मछुआरों को दी जाएगी राहत: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

अश्वनी वर्मा . शिमला

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायकों द्वारा देहरा क्षेत्र में मछुआरों की आजीविका, नदियों में बढ़ती सिल्ट और ड्रेजिंग के मुद्दे उठाने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठा रही है। सबसे पहले देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर ने देहरा में सिल्ट के कारण मछुआरों को रही दिक्कतों का मामला उठाया। इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि देहरा का अधिकांश क्षेत्र भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के अधीन आता है, इसलिए इस विषय पर उससे समन्वय जरूरी है, वहीं राज्य ने ड्रेनेज पॉलिसी के तहत उन स्थानों की पहचान शुरू की है जहां नदियों और खड्डों में अधिक सिल्ट जमा हो रही है लेकिन ड्रेजिंग नहीं हो पा रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मछुआरों के हित में बजट में योजना लाई गई है, जिसके तहत वर्ष में दो महीने मछली पकड़ने पर रोक के दौरान भी उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी और सिल्ट से मछलियों को हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए गए हैं, साथ ही देहरा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान भविष्य में किया जाएगा। फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानिया के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रेजिंग के लिए वन और माइनिंग विभाग के साथ संयुक्त रूप से वैज्ञानिक मैपिंग करवाई जाएगी जिसमें संबंधित जिला उपायुक्त व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा, जबकि झंडुता के विधायक जीत सिंह कटवाल के प्रश्न पर कोऑपरेटिव फेडरेशन की जांच के निर्देश देने की बात कही। बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने सिल्ट से फसलों और घरों को हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाते हुए सुकेती खड्ड के चौनलाइजेशन की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिल्ट की समस्या पूरे प्रदेश में है और कुल्लू में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी सफलता के बाद इसे अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ की अनुपस्थिति में धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर के सवाल पर मुख्यमंत्री ने बताया कि ब्यास नदी सहित विभिन्न खड्डों में ड्रेजिंग के लिए 42 साइटें चिन्हित की गई हैं और मनाली को प्राथमिकता दी गई है, हालांकि इसके लिए वन स्वीकृति आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने नूरपुर के विधायक रणबीर सिंह निक्का के अनुपूरक सवाल के जवाब में कहा कि कृषि कार्यों के लिए अधिकृत ट्रैक्टर चालकों के लिए नई नीति लाने पर विचार किया जा रहा है ताकि उन्हें राहत मिल सके। इसमें ट्रैक्टर चालकों को खनन नियमों में ढील देने पर विचार किया जाएगा। केवल सिंह पठानिया ने ट्रैक्टर चालकों का पुलिस द्वारा कथित उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ब्यास नदी में बार-बार होने वाले नुकसान और 2023 की आपदा के दौरान मलबा हटाने में लगी मशीनरी को लेकर सवाल उठाए, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चैनलाइजेशन के बजाय ड्रेजिंग पर ध्यान दे रही है और यदि किसी स्थान पर अनियमितता हुई है तो उसकी जानकारी देने पर जांच करवाई जाएगी।

आयुष मेला, लोधीमाजरा (बद्दी) में आईआरजी के प्रोजेक्ट प्रत्यूष्या की रिपोर्ट का अनावरण

प्रवीण शर्मा . बद्दी

दिनांक 29 मार्च 2026 को बद्दी के लोधीमाजरा में आयोजित आयुष मेले के अवसर पर इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड ग्रोथ (आईआरजी) के प्रोजेक्ट प्रत्यूष्या की विस्तृत रिपोर्ट का औपचारिक रूप से अनावरण किया गया।

इस अवसर पर नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक हरदीप सिंह बावा, उपमंडलीय आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ. नीरज जुल्का, डॉ. बबीता तथा डॉ. कंचन चौहान द्वारा रिपोर्ट का अनावरण किया गया।

यह रिपोर्ट परियोजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिसमें बेसलाइन एवं एंडलाइन अध्ययन के आधार पर प्रमुख निष्कर्ष, प्रगति संकेतक तथा परियोजना के समग्र प्रभाव को दर्शाया गया है।

रिपोर्ट का अनावरण प्रोजेक्ट प्रत्यूष्या के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा, क्योंकि इसके माध्यम से परियोजना के मापनीय परिणामों को प्रस्तुत किया गया तथा भविष्य की योजना एवं क्रियान्वयन के लिए साक्ष्य-आधारित दिशा प्रदान की गई। इस अवसर पर रिपोर्ट को संबंधित हितधारकों के साथ भी साझा किया गया।

इस आयुष मेले के दौरान स्थानीय समुदाय के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें 300 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधियां प्रदान की गईं। साथ ही मेले में आयुर्वेदिक उत्पादों, औषधीय पौधों एवं जड़ी-बूटियों की प्रदर्शनी लगाई गई तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) सामग्री के माध्यम से लोगों को निवारक स्वास्थ्य देखभाल और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के महत्व के बारे में जागरूक किया गया।

कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली तथा लोगों ने आयुष पद्धति के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया।

नव नियुक्त पदाधिकारियों को समर्पण से कार्य करने का आह्वान

प्रचण्ड समय . शिमला

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने आज नव नियुक्त पार्टी पदाधिकारियों को संगठन के प्रति समर्पण से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान करने का आग्रह करते हुए कहा कि पदाधिकारियों पर संगठन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे उन्हें पूरी कुशलता से निभाना होगा।

इस दौरान पार्टी के नव नियुक्त पदाधिकारी संगठन महामंत्री विनोद जिंटा,उपाध्यक्ष अमित नंदा,हरिकृष्ण हिमराल,धर्मेंद्र धामी, यशपाल तनाईक, यादोपति ठाकुर,उपेंद्र कांत मिश्रा,अनीता वर्मा,ज्योति खन्ना, विकास ठाकुर सहित कई अन्य पदाधिकारियों ने अपनी इस नियुक्ति के लिए केंद्रीय आलाकमान, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार को फूलों के गुलदस्ते भेंट किये।

बाद में विनय कुमार ने संगठन महामंत्री विनोद ज़िंटा व अमित नंदा उपाध्यक्ष प्रशासन को उनके कक्ष में जाकर उनकी कुर्सी पर उन्हें विराजमान किया व उन्हें इस जिम्मेदारी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संगठन महामंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि विनोद ज़िंटा छात्र राजनीति एनएसयूआई से लेकर युवा कांग्रेस के पदों पर रहते हुए संगठन के कामकाज से भली भांति परिचित है। इनका लंबा अनुभव संगठन के बेहतर कामकाज में सार्थक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि विनोद ज़िंटा के साथ उनका संगठन को बहुत लंबा सहयोग भी रहा है। युवा नेतृत्व उनकी क्षमता को दर्शाता है।

विनय कुमार ने अमित नंदा को भी उनकी कुर्सी पर विराजमान करते हुए कहा कि नंदा बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है। उन्हें पीसीसी में उपाध्यक्ष के पद पर साथ में कार्यलय प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वह अपने अनुभव से पीसीसी को बेहतर प्रशासन देंगे।

भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने लोकसभा में पिंजौर—बद्दी—नालागढ़ सड़क की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया

प्रचण्ड समय . शिमला

भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री सुरेश कुमार कश्यप ने लोकसभा में नियम 377 के तहत हिमाचल प्रदेश के पिंजौर–बद्दी–नालागढ़ सड़क मार्ग की अत्यंत दयनीय स्थिति का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह मार्ग हिमाचल प्रदेश के बद्दी–बरोटीवाला–नालागढ़ (BBN) औद्योगिक क्षेत्र को हरियाणा और चंडीगढ़ से जोड़ने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है, जो प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ के रूप में कार्य करता है।

सांसद सुरेश कश्यप ने सदन में बताया कि BBN क्षेत्र एशिया के प्रमुख औद्योगिक हब में से एक है, जहाँ 2000 से अधिक उद्योग संचालित हैं और प्रतिदिन लगभग 30,000 से अधिक वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। इसके बावजूद इस सड़क की वर्तमान स्थिति अत्यंत खराब है, जिससे आम जनता, उद्योगों और कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने जानकारी दी कि इस सड़क के चार-लेन निर्माण कार्य की शुरुआत अप्रैल 2022 में की गई थी, जिसे सितंबर 2024 तक पूरा किया जाना था। इसके लिए प्रारंभिक रूप से लगभग 556 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था, जो अब बढ़कर 650–670 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। इसके बावजूद वर्ष 2026 तक भी यह परियोजना अधूरी पड़ी है, जो राज्य सरकार की गंभीर लापरवाही और प्रशासनिक विफलता को दर्शाती है।

सांसद कश्यप ने यह भी बताया कि जानकारी के अनुसार लगभग 40–45 प्रतिशत कार्य होने के बाद ठेकेदार द्वारा काम छोड़ दिया गया, और अब तक 10 से अधिक बार टेंडर प्रक्रिया रद्द या स्थगित हो चुकी है। परिणामस्वरूप निर्माण कार्य पूरी तरह ठप पड़ा है। वर्तमान में सड़क की हालत अत्यंत खराब है—जगह-जगह गड्ढे, अधूरी लेन, जलभराव और भारी ट्रैफिक जाम आम बात हो गई है।

उन्होंने कहा कि इस स्थिति के कारण न केवल आम नागरिकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उद्योगों को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है और आपातकालीन सेवाएँ भी प्रभावित हो रही हैं।

सांसद सुरेश कश्यप ने सरकार से आग्रह किया कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के लिए ठोस और समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जाए, ताकि क्षेत्र की जनता और उद्योगों को राहत मिल सके।

उन्होंने प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है और इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है।

एलपीजी एवं पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य

प्रचण्ड समय . शिमला

जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जिला शिमला नरेंदर धीमान ने आज यहां बताया कि जिला शिमला में वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत एलपीजी एवं पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को लेकर स्थिति सामान्य एवं नियंत्रित बनी हुई है।

यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न परिस्थितियों के कारण एलपीजी आपूर्ति पर कुछ प्रभाव पड़ा है, परन्तु जिला में घरेलू गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है तथा पर्याप्त मात्रा में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। वर्तमान में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पूर्व की भांति नियमित रूप से की जा रही है।

व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति 50 प्रतिशत आरम्भ

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को भी सुचारू किया गया है तथा अब व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति 50 प्रतिशत आरम्भ कर दी गई है| जिला के होटल, रेस्तरां एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पर्याप्त मात्रा में व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि वे घरेलू सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए न करें तथा ईंधन के वैकल्पिक साधनों का भी उपयोग करें। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गैस एजेंसियों, होटलों एवं रेस्तरां में निरीक्षण कर कालाबाजारी एवं जमाखोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

न्यूज ब्रीफ..

शिमला में पेंशनरों का प्रदर्शन, लंबित भुगतान नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन

अश्वनी वर्मा, शिमला . हिमाचल प्रदेश में लंबित वित्तीय देनदारियों को लेकर पेंशनरों का असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। सोमवार को शिमला में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान चौड़ा मैदान में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में पेंशनरों ने धरना-प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई।
प्रदर्शन कर रहे पेंशनरों ने आरोप लगाया कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कई कर्मचारियों को अभी तक ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का भुगतान नहीं किया गया है। उनका कहना है कि लंबे समय से इन देनदारियों के लंबित रहने से बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि 13 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की बकाया राशि और 44 महीनों के एरियर का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है। इसके अलावा पेंशनरों के करोड़ों रुपये के चिकित्सा बिल भी पिछले करीब तीन वर्षों से लंबित पड़े हैं, जिससे कई बुजुर्गों के लिए इलाज कराना मुश्किल हो गया है।
धरने के दौरान पेंशनरों ने राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द उनकी वित्तीय देनदारियों का भुगतान नहीं किया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे और इसके लिए व्यापक स्तर पर रणनीति बनाई जाएगी।
संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर पहले भी कई बार सरकार के समक्ष मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि पेंशनरों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।
इस मामले में राज्य सरकार की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि पेंशनरों ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला लेगी और लंबित भुगतान जल्द जारी किया जाएगा।

हिमाचल में 10 साल सेवा पूरी कर चुकीं 7454 आशा वर्करों को नियमित करने की कोई नीति नहीं: सरकार

शिमला . हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में आशा वर्करों को नियमित करने की फिलहाल कोई नीति विचाराधीन नहीं है। यह जानकारी सोमवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनी राम शांडिल ने विधानसभा में नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा के सवाल के लिखित जवाब में दी।
सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 31 दिसंबर 2025 तक प्रदेश में 7454 आशा वर्कर ऐसी हैं, जिन्होंने 10 वर्ष या उससे अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया है। विधायक हरदीप सिंह बावा ने सरकार से पूछा था कि 10 साल सेवा पूरी कर चुकी आशा वर्करों के लिए कोई स्थायी नीति बनाने पर विचार किया जा रहा है या नहीं। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि ऐसी कोई नीति फिलहाल विचाराधीन नहीं है।
सरकार ने यह भी बताया कि आशा वर्करों का चयन तय दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम आठवीं पास और शहरी क्षेत्रों में दसवीं पास महिलाएं आशा वर्कर के रूप में चयनित होती हैं। सरकार का कहना है कि आशा वर्कर मिडवाइफ के कार्यों के लिए पात्र नहीं हैं।
विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में मिडवाइफ के कुल 503 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 182 पद भरे हुए हैं, जबकि 321 पद खाली हैं। जिला स्तर पर कुल्लू में सबसे अधिक 90 पद रिक्त हैं। इसके अलावा शिमला में 45, सोलन में 26, हमीरपुर में 21, चंबा में 19, किन्नौर में 18 और सिरमौर में 17 पद खाली हैं।

बद्दी यूनिवर्सिटी में "इमनेशन 2026" वार्षिक तकनीकी महोत्सव का भव्य आयोजन

पुष्पिंदर कौर . बीबीएन

बद्दी यूनिवर्सिटी में वार्षिक तकनीकी उत्सव "इमनेशन 2026" का शुभारंभ प्रो. (डॉ.) जे.के. शर्मा, माननीय कुलपति, बद्दी यूनिवर्सिटी द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। इस वर्ष आयोजन की थीम "विकसित भारत 2047" रही, जिसके अंतर्गत नवाचार, आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया।

इसके बाद तकनीकी प्रदर्शनी में छात्रों ने अपने मॉडल्स और तकनीकी प्रोजेक्ट्स का शानदार प्रदर्शन किया। कला प्रदर्शनी में छात्रों ने कचरे से सुंदर कलाकृतियां और पेंटिंग्स बनाकर अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया। साहित्यिक कार्यक्रमों ने भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया।

शाम के सत्र में छात्रों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुतियां, नाटक और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। गिद्दा, नाटी और भांगड़ा जैसी प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में विशेष आकर्षण जोड़ा और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया।

शाम को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राम कुमार चौधरी (विधायक, दून) की गरिमामयी

उपस्थिति रही। इसके बाद मशहूर पंजाबी गायक शिवजोत ने अपने शानदार गानों से माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया और छात्रों को भरपूर मनोरंजन प्रदान किया।

इस अवसर पर प्रो. (डॉ.) टी.आर. भारद्वाज (कुलपति सलाहकार), प्रो. (डॉ.) खुशमीत कुमार (रजिस्ट्रार, बद्दी यूनिवर्सिटी), सभी डीन और विभागाध्यक्षों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। डॉ. सुषमा सिंह (छात्र कल्याण अधिकारी), डॉ. भारतेन्दु शर्मा, श्री रोहित शर्मा (जनसंपर्क अधिकारी) तथा श्री पांशुल जमवाल भी उपस्थित रहे। पूरे आयोजन का समापन उत्साह और उल्लास के साथ हुआ।

कार्यक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी और उनके उत्साह ने इसे एक यादगार आयोजन बना दिया। छात्रों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से उन्हें सीखने, टीम वर्क, नेतृत्व और नवाचार की समझ विकसित करने का अवसर मिलता है, जो उनके भविष्य के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा।

हिमाचल को वित्तीय दिवालियापन की ओर धकेल रही कांग्रेस सरकार – विपिन परमार

प्रचण्ड समय . शिमला

भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ नेता एवं विधायक विपिन परमार, मुख्य प्रवक्ता राकेश जमवाल, मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा एवं मीडिया संयोजक कर्ण नंदा उपस्थित रहे। बैठक में प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन, वित्तीय स्थिति और जनविरोधी नीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

इस अवसर पर भाजपा नेता विपिन परमार ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को वित्तीय दिवालियापन की ओर धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लेने के बावजूद सरकार जनकल्याणकारी कार्य करने में पूरी तरह विफल रही है। केंद्र सरकार से भारी भरकम सहायता मिलने के बावजूद प्रदेश की जनता को किसी प्रकार की राहत या सुविधा नहीं मिल पा रही है।

मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी, पेंशनभोगी एवं आउटसोर्स कर्मचारी आज अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन आज तक एक भी वादा धरातल पर नहीं उतरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार केवल झूठ और धोखे की राजनीति कर रही है।

मुख्य प्रवक्ता राकेश जमवाल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश का युवा आज भी बेरोजगारी की मार झेल रहा है।

पहली कैबिनेट में 5 लाख नौकरियां देने का वादा करने वाली कांग्रेस आज नौकरियां देने के बजाय अवसर छीनने का काम कर रही है। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है और सरकार पूरी तरह मौन बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि यह सरकार केवल अपने चहेतों तक सीमित होकर रह गई है।

भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की नीतियों से पूरी तरह निराश है और आने वाले समय में इसका जवाब जनता अवश्य देगी।

आपदा न्यूनीकरण के तहत 20.70 करोड़ के 4 प्रस्तावों पर की चर्चा

प्रचण्ड समय . शिमला

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित बैठक में जिला से राज्य आपदा न्यूनीकरण के तहत लगभग 20.70 करोड़ रुपए के 04 प्रस्तावों को भेजने को लेकर गहन चर्चा की गई। इन 04 प्रस्तावों में लगभग 1.86 करोड़ रुपए का सुरु गांव में बाढ़ से बचाव के उपाय हेतु प्रोजेक्ट शामिल है । इसी प्रकार, इनमे 9.33 करोड़ रुपए से रामचंद्र चौक से हेनॉल्ट पब्लिक स्कूल के बीच सड़कों के आसपास धंसते हुए क्षेत्र के लिए न्यूनीकरण उपाय और स्थिरीकरण की योजना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, इन प्रस्तावों में 9.05 करोड़ रुपए से सुन्नी में शिमला-मंडी मार्ग पर सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण के उपाय तथा 43.94 लाख रुपए से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुफरी के भवन की रेट्रोफिटिंग का प्रस्ताव शामिल है। उपायुक्त ने सम्बंधित अधिकारियों को इन प्रस्तावों में एक सप्ताह के भीतर सभी कमियों को दूर कर पुनः बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि इन मामलों को आगामी कार्यवाई के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजा जा सके। बैठक में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पहले भेजे गए 06 प्रस्तावों में से 10.63 करोड़ रुपए के 02 प्रस्तावों को अनुशंसा प्राप्त हुई है जबकि 2.98 करोड़ रुपए के 02 मामलों में सैद्धांतिक मंजूरी मिली है और 16.72 करोड़ रुपए के 02 मामलों को वापस भेजा गया है ताकि उनमें जो कमियां हैं उन्हें दूर करके पुनः राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजा जा सके।

हरियाणा में ग्रुप-डी के चयनित अभ्यर्थियों का बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाएगा

राजेंद्र सिंह जादौन . चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत चयनित कॉमन कैडर ग्रुप-डी के 13,246 अभ्यर्थियों का बायोमीट्रिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। इन कर्मचारियों का बायोमीट्रिक सत्यापन राज्य के विभिन्न मंडलों में मंडल आयुक्तों तथा पंचकूला में उपायुक्त, पंचकूला के स्तर पर किया जाएगा। इस सिलसिले में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अंबाला मंडल में 20 अप्रैल, 2026 को 1,451 अभ्यर्थियों का बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इनमें 1,417 अभ्यर्थी विभिन्न विभागों में तैनात हैं जबकि 34 अभ्यर्थी मंडल आयुक्त कार्यालय से संबद्ध हैं। करनाल मंडल में 21 अप्रैल, 2026 को कुल 1,662 अभ्यर्थियों का सत्यापन किया जाएगा। इनमें से 1,584 अभ्यर्थी विभागों में कार्यरत हैं जबकि 78 अभ्यर्थी मंडल आयुक्त कार्यालय से संबद्ध हैं। रोहतक मंडल में 22 और 23 अप्रैल, 2026 को 3,750 अभ्यर्थियों का सत्यापन किया जाएगा। इनमें से 3,389 अभ्यर्थी विभागों में कार्यरत हैं तथा 361 अभ्यर्थी मंडल आयुक्त कार्यालय से संबद्ध हैं। हिसार मंडल में 24 और 27 अप्रैल, 2026 को 2,918 अभ्यर्थियों का बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इनमें 2,585 अभ्यर्थी विभागों में कार्यरत हैं जबकि 333 अभ्यर्थी मंडल आयुक्त कार्यालय से संबद्ध हैं। फरीदाबाद मंडल में 28 अप्रैल, 2026 को 960 अभ्यर्थियों का सत्यापन किया जाएगा, जिनमें 954 विभागों में कार्यरत हैं तथा 6 अभ्यर्थी मंडल आयुक्त कार्यालय से संबद्ध हैं। गुरुग्राम मंडल में 29 अप्रैल, 2026 को 1,841 अभ्यर्थियों का उम्मीदवारों का सत्यापन किया जाएगा, जिनमें 1,801 विभागों में कार्यरत हैं तथा 40 अभ्यर्थी मंडल आयुक्त कार्यालय से संबद्ध हैं।
पंचकूला में 30 अप्रैल, 2026 को 664 अभ्यर्थियों का बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इनमें चंडीगढ़, पंचकूला तथा विभिन्न विभागों एवं मंडल आयुक्त कार्यालयों से सम्बद्ध शेष अभ्यर्थी शामिल होंगे।

हिमाचल में अंधड़, ओलावृष्टि और आसमानी बिजली का अलर्ट, बारिश-बर्फबारी से ठंड बढ़ी

अश्वनी वर्मा . शिमला

हिमाचल प्रदेश में मौसम के तेवर कड़े बने हुए हैं और राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड का असर बढ़ गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में रुक-रुक कर बर्फबारी हो रही है, जबकि कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 5 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है और कई जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि तथा आसमानी बिजली को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

राज्य के लाहौल-स्पीति जिले के मुख्यालय केलंग में 2 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। इसके अलावा रोहतांग दर्रे सहित किन्नौर, कुल्लू और चंबा की ऊंची चोटियों पर भी हिमपात हुआ है। शिमला, मनाली और अन्य मध्य व निचले इलाकों में सुबह से बादल छाए रहे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो सराहन में 32.7 मिमी, कसौली में 32.0 मिमी, धर्मपुर में 27.6 मिमी, पच्छाद में 20.4 मिमी, सोलन में 18.4 मिमी, मनाली में 14.0 मिमी, सेओबाग में 11.4 मिमी, रोहड़ू में 10.0 मिमी, कंडाघाट में 8.4 मिमी, भुंतर में 7.8 मिमी और धर्मशाला में 7.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा शिमला में 4.4 मिमी और सुंदरनगर में 4.0 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश के औसतन न्यूनतम तापमान में 1.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान शिमला में 11.8 डिग्री, सुंदरनगर में 12.1 डिग्री, भुंतर में 9.3 डिग्री, कल्पा में 3.0 डिग्री, धर्मशाला में 9.5 डिग्री, ऊना में 15.3 डिग्री, नाहन में 15.3 डिग्री, केलंग में 1.5 डिग्री, पालमपुर में 13.5 डिग्री, सोलन में 11.0 डिग्री, मनाली में 7.1 डिग्री, कांगड़ा में 15.2 डिग्री, मंडी में 13.3 डिग्री और बिलासपुर में 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठंड बढ़ने से पहाड़ी इलाकों में लोग फिर से गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं, जबकि मैदानी और निचले क्षेत्रों में भी मौसम ठंडा बना हुआ है।

मौसम विभाग के अनुसार आज कई स्थानों पर अंधड़, ओलावृष्टि और आसमानी बिजली के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर अन्य आठ जिलों में आज अलर्ट रहेगा। इनमें शिमला, मंडी और कुल्लू में ओलावृष्टि, आसमानी बिजली व 40 से 60 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से आंधी चलने का ओरेंज अलर्ट रहेगा। जबकि कांगड़ा, चम्बा, हमीरपुर, बिलासपुर व ऊना में येलो अलर्ट रहेगा। इसके बाद, 31 मार्च को कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 1 और 2 अप्रैल को मौसम खराब रहेगा, लेकिन किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वहीं 3 और 4 अप्रैल को फिर से कई जिलों में अंधड़ और आसमानी बिजली की चेतावनी जारी की गई है। 5 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

हमीरपुर डिपो में 37 चालकों की कमी, एक बस रूट अस्थायी रूप से बंद

अश्वनी वर्मा . शिमला

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के हमीरपुर डिपो में चालकों की कमी के कारण एक बस रूट अस्थायी रूप से बंद किया गया है। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में विधानसभा में दी।

सरकार के अनुसार हमीरपुर डिपो में चालकों के 216 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में 179 चालक कार्यरत हैं और 37 पद खाली हैं। चालकों की कमी के कारण 1 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक हमीरपुर से शिमला वाया लम्बलू सुबह 5 बजकर 10 मिनट पर चलने वाली बस सेवा अस्थायी रूप से बंद रखी गई।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस बस रूट को दोबारा शुरू करना यात्रियों की संख्या और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों के 3476 पद खाली, फिलहाल भर्ती पर कोई निर्णय नहीं

हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में पुरुष और महिला स्वास्थ्य कर्मियों के कुल 3476 पद खाली हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने विधायक विनोद कुमार के सवाल के लिखित जवाब में विधानसभा में दी।

सरकार के अनुसार इनमें 1920 पद पुरुष स्वास्थ्य कर्मियों के और 1556 पद महिला स्वास्थ्य कर्मियों के रिक्त हैं। मंत्री ने बताया कि फिलहाल इन पदों को भरने का मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है। हालांकि विभाग में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों और रोगी मित्रों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि पुरुष स्वास्थ्य कर्मियों के पदों पर आखिरी बार वर्ष 2019 में 80 पदों के लिए भर्ती हुई थी। इसके बाद वर्ष 2022 में 3 पद और वर्ष 2023 में 1 पद के लिए भर्ती की गई थी।

कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में 937 पद खाली, भर्ती पर विचार जारी

प्रदेश के कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में विभिन्न श्रेणियों के कुल 937 पद रिक्त हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री ने विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में विधानसभा में दी। सरकार ने बताया कि 31 जनवरी 2026 तक बैंक में 937 पद खाली हैं और इन्हें भरने का मामला विचाराधीन है। इन पदों को बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार पंजीयक सहकारी सभाएं की पूर्व अनुमति के बाद बैंक के सेवा नियमों के तहत निदेशक मंडल द्वारा तय एजेंसी के माध्यम से भरेगा।

राज्यपाल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से की भेंट

प्रचण्ड समय . शिमला

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। राज्यपाल के रूप में प्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त प्रधानमंत्री के साथ उनकी यह पहली शिष्टाचार भेंट है। बैठक के दौरान राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश के विकास और जनकल्याण से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया। उन्होंने 'नशा-मुक्त हिमाचल अभियान' और 'टीबी-मुक्त हिमाचल अभियान' जैसे महत्वपूर्ण पहलों से प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है। लोगों को प्राकृतिक खेती पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया

जा रहा है जिससे बड़ी संख्या में किसान और बागवान रसायन मुक्त कृषि पद्धति को अपना रहे हैं। उन्होंने इन पहलों को और अधिक बढ़ावा देने तथा विस्तार प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहाड़ी राज्य हिमाचल पूरी तरह से शून्य लागत और पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धति को अपनाकर दीर्घकालिक पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करेगा। कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि इन विकासात्मक पहलों को गति देने के लिए केंद्र सरकार का निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने राज्य और केंद्र के बीच समन्वित प्रयासों के महत्व पर बल देते हुए कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश में समग्र विकास, जनकल्याण और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत

भगवान श्री राम का नेतृत्व कौशल

भगवान श्री राम भारतीय संस्कृति, धर्म और आदर्श जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि नेतृत्व के दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रेरणादायक है। रामायण में वर्णित श्री राम का जीवन एक आदर्श नेता के गुणों का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनका नेतृत्व न्याय, मर्यादा, त्याग, धैर्य और सहानुभूति जैसे उच्च मूल्यों पर आधारित था।

प्रोफेसर (डॉ.) प्रमोद शर्मा

श्री राम का नेतृत्व सबसे पहले उनके कर्तव्यपरायणता में दिखाई देता है। जब उन्हें अयोध्या का राजा बनने का अवसर मिला, तब उन्होंने अपने पिता दशरथ के वचन की रक्षा के लिए बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। यह निर्णय बताता है कि एक सच्चा नेता अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों और सिद्धांतों को प्राथमिकता देता है। आज के नेतृत्व में यह गुण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे विश्वास और नैतिकता की स्थापना होती है।

श्री राम के नेतृत्व का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी है। उन्होंने जीवनभर सत्य और धर्म का पालन किया, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हों। उनका यह गुण उन्हें "मर्यादा पुरुषोत्तम" बनाता है। एक नेता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने वचनों और कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखे, जिससे अनुयायियों में विश्वास उत्पन्न हो सके।

उनकी सहानुभूति और करुणा भी उनके नेतृत्व का प्रमुख आधार थी। श्री राम ने हमेशा अपने सहयोगियों, प्रजा और यहां तक कि शत्रुओं के प्रति भी सम्मान और दया का व्यवहार किया। जब उन्होंने विभीषण को शरण दी, तब उन्होंने यह दिखाया कि एक सच्चा नेता सभी को समान अवसर देता है और न्याय के आधार पर निर्णय लेता है। यह गुण आधुनिक नेतृत्व में समावेशिता अथवा इन्क्लूसिवनेस और विविधता यानी डायवर्सिटी को बढ़ावा देता है।

श्री राम का नेतृत्व टीम निर्माण और सहयोग पर भी आधारित था।

उन्होंने वनवास के दौरान हनुमान, सुग्रीव और अन्य वानर सेना के साथ मिलकर एक मजबूत टीम बनाई। उन्होंने हर सदस्य की क्षमता को पहचाना और उसे सही दिशा में उपयोग किया। उदाहरण के लिए, हनुमान की शक्ति और बुद्धिमत्ता का उपयोग सीता की खोज में किया गया। यह दर्शाता है कि एक प्रभावी नेता अपने टीम के सदस्यों की ताकत को पहचानकर उन्हें सही भूमिका देता है।

निर्णय लेने की क्षमता भी श्री राम के नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण गुण था। उन्होंने हर परिस्थिति में संतुलित और विवेकपूर्ण निर्णय लिए। चाहे वह सीता की खोज के लिए समुद्र पार करने का निर्णय हो या रावण के साथ युद्ध करने का, उन्होंने हर कदम सोच-समझकर उठाया। यह गुण आज के प्रबंधकीय नेतृत्व में रणनीतिक सोच अथवा स्ट्रेटिजिक थिंकिंग का आधार है।

श्री राम का धैर्य और आत्मसंयम भी उनके नेतृत्व को विशेष बनाता है। वनवास के दौरान उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने धैर्य को नहीं खोया। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। यह गुण किसी भी नेता के लिए आवश्यक है, क्योंकि संकट के समय में वही नेता सफल होता है जो धैर्य और संतुलन बनाए रखता है।

उनका नेतृत्व न्यायप्रियता पर आधारित था। जब उन्होंने रावण का वध किया, तो यह केवल व्यक्तिगत बदले के लिए नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना के लिए था। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनके निर्णय समाज के हित में हों। एक आदर्श नेता वही होता है जो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय लेता है।

श्री राम का संचार कौशल अर्थात कम्युनिकेशन स्किल्स भी अत्यंत प्रभावशाली था। वे स्पष्ट, सरल और प्रभावी तरीके से अपनी बात रखते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ खुलकर संवाद किया और उनकी भावनाओं को समझा। एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सके और दूसरों की बात सुनने की क्षमता रखता हो।

उनकी प्रेरणादायक क्षमता अर्थात इंस्पिरेशनल पावर भी उल्लेखनीय थी। श्री राम ने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में वानर सेना ने असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को भी संभव कर दिखाया। यह दर्शाता है कि एक नेता अपनी टीम को प्रेरित करके उन्हें उच्चतम प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

श्री राम का नेतृत्व त्याग और बलिदान का प्रतीक भी है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर समाज और धर्म की रक्षा की। उनका यह गुण बताता है कि एक सच्चा नेता अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हित में कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त, श्री राम में दूरदर्शिता अर्थात विज़न का भी अद्भुत गुण था। उन्होंने केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान ही नहीं किया, बल्कि भविष्य के लिए भी एक आदर्श समाज की नींव रखी। उनके शासनकाल को "रामराज्य" के रूप में जाना जाता है, जो न्याय, शांति और समृद्धि का प्रतीक है।

अंततः, श्री राम का नेतृत्व आदर्श मूल्यों पर आधारित था, जिसमें धर्म, सत्य, करुणा, न्याय और त्याग का समावेश था। उनका जीवन यह सिखाता है कि एक सच्चा नेता केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है।

इस प्रकार, भगवान श्री राम का नेतृत्व आज के आधुनिक प्रबंधन और नेतृत्व सिद्धांतों के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। उनके गुण हमें यह सिखाते हैं कि नेतृत्व केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है, और एक सफल नेता वही होता है जो अपने आदर्शों और मूल्यों के प्रति अडिग रहता है।

प्रोफेसर (डॉ.) प्रमोद शर्मा (पू. हि प्र से)
निर्देशक, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, समरहिल, शिमला हि प्र
ईमेल:pramodhimachal@gmail.com
मो. 9418055158

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में तीसरे विकल्प की संभावना : चुनौतियाँ

लेखक : विरेंद्र सिंह

हिमाचल प्रदेश की राजनीति को यदि एक वाक्य में समझना हो, तो यह कहा जा सकता हैं कि यहाँ सत्ता का खेल मुख्यतः दो दलों–भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के बीच ही सीमित रहा हैं। 1985 के बाद से राज्य में लगभग हर विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन (Anti-Incumbency) की परंपरा रही हैं, जिसने इस द्विदलीय प्रणाली को और मजबूत किया हैं। हिमाचल प्रदेश के गठन 1971 के बाद शुरुआती दशकों में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का दबदबा रहा। जिसका मुख्य कारण उस समय विपक्ष में एकता का अभाव था और भारतीय जनसंघ जैसे दल सीमित प्रभाव रखते थे। 1977 में देशभर में आपातकाल के बाद बने महौल में जनता पार्टी ने हिमाचल में भी सत्ता हासिल की, लेकिन यह भी स्थायी "तीसरा विकल्प" नहीं बन सका। यह राष्ट्रीय लहर का परिणाम था।

1980 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के उभार के साथ हिमाचल की राजनीति लगभग दो गुटों में विभाजित हो गई। इसके बाद के चुनाव परिणामों में 1985 विधानसभा चुनाव में काँग्रेस को 58/68 सीटों का भारी बहुमत प्राप्त हुआ। 1990 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत के साथ 46 सीटें प्राप्त हुई, 1993 के विधानसभा चुनाव में काँग्रेस पार्टी ने फिर से 52 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त किया। 1998 के चुनाव में भाजपा व काँग्रेस को 31,31 सीटें प्राप्त हुई व "हंग विधानसभा" बनी। इन आकड़ों का अध्ययन करने के बाद यह कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक सत्ता मुख्यत दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बीच सिमट चुकी हैं। तीसरे विकल्प की सफलता 1998 में देखने को मिली, जब "हिमाचल विकास पार्टी"(HVP) ने 4 सीटें जीत कर "किंगमेकर" की भूमिका निभाई। इस स्थिति में HVP ने भाजपा को समर्थन दिया। यह हिमाचल के इतिहास में पहली व आखरी बार हुआ था, जब किसी क्षेत्रीय दल ने सत्ता गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, लेकिन कुछ समय बाद ही यह दल भी कमजोर पड़ गया और अततः मुख्यधारा में विलीन हो गया।

2003 से 2022 तक चुनावों में तीसरे विकल्प की स्थिति कमजोर होती गई। 2003 में काँग्रेस 43, भाजपा 16, अन्य 09, 2007 में भाजपा 41, काँग्रेस 23 अन्य 04, 2012 काँग्रेस 36, भाजपा 26 अन्य 06, 2017 में भाजपा 44, काँग्रेस 21, अन्य 03 व 2022 के विधानसभा चुनाव में काँग्रेस 40, भाजपा 25 व अन्य 03। हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प की सीटें कभी भी 10%से अधिक नहीं रही व वोट प्रतिशत भी 10-15% के बीच ही रहा।

वामपंथी दल cpim का कुछ क्षेत्रों में प्रभाव अवश्य हैं लेकिन राज्य स्तरीय नहीं।

हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प के असफल होने के मुख्य कारण

दिल्ली व पंजाब में आम आदमी पार्टी की सफलता एक उदाहरण जरूर हैं, लेकिन हिमाचल की भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। हिमाचल प्रदेश में केवल 68 विधानसभा सीटें हैं यहाँ चुनाव सीधा व्यक्ति व पार्टी के बीच होता हैं, न की जटिल गठबंधन समीकरणों पर। इसके साथ काँग्रेस व भारतीय जनता पार्टी का पंचायत स्तर पर मजबूत संगठन हैं, जो तीसरे विकल्प के पास नहीं होता हैं। इसके साथ तीसरे विकल्प के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं रहा, जैसा काँग्रेस व भाजपा का पास होता हैं। इसके साथ लोगों के बीच भी यह धारणा रही हैं कि तीसरे विकल्प को वोट देना, वोट की बर्बादी समझते हैं। जिससे तीसरे विकल्प को नुकसान होता हैं।

क्या हिमाचल में तीसरा विकल्प उभर सकता हैं?

संभावना को पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन कुछ तथ्यों पर बात की जा सकती हैं।

वर्तमान स्थिति 2026 के परिप्रेक्ष्य में तीसरे विकल्प की सत्ता में आने की संभवना बहुत कम (5-10%) हैं।

"किंगमेकर" बनाने की संभवना सीमित, लेकिन संभव 15-20% यदि चुनाव त्रिकोणीय हो जाए। भाजपा के पूर्व मंत्री डॉ रामलाल मार्कडेय का बयान अखबार में आने से राजनीतिक गलियारों में तीसरे मोर्चे की बहस काफ़ी तेज हो गई हैं। रामलाल मार्कडेय ने यह भी कहा, कि इस मुहिम में एक व्यक्ति नहीं हूँ बल्कि बहुत सारे व्यक्ति इस मुहिम के लिए काम कर रहे हैं। आज तक जो तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में जो मोर्चा बना भी हैं वो बहुत कामयाब नहीं रहा हैं। पंडित सुखराम ने "हिमाचल विकास पार्टी" बनाई और उन्हें विधानसभा की कुछ सीटें हासिल करने में कामयाबी भी मिली। उसके बाद भी थोड़े बहुत प्रयास जरूर हुआ, परंतु उसका बहुत बड़ा लाभ राजनीतिक रूप से नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश में यदि तीसरे मोर्चे की 10-15 सीटें आ भी जाती हैं तो उससे उनका वर्चस्व जरूर बढ़ेगा, लेकिन यह असंभव जरूर प्रतीत होता हैं पर राजनीतिक गलियारों में कुछ भी हो सकता हैं। और यह सब भविष्य के गर्त में छिपा हुआ हैं। पंडित सुखराम जी की पार्टी जो उस समय में 4 सीटें लाने में कामयाब रहे, उसका बहुत बड़ा कारण स्वयं पंडित जी का प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा।

दूसरी महत्वपूर्ण बात नया राजनीतिक दल बनाने के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण हैं नई पार्टी को खड़ा करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती हैं। नए मोर्चे में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, उसकी जनता के बीच कितनी पेठ हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीसरे मोर्चे की बात की जाए तो इसमें समय भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि नया राजनीतिक दल चुनाव से 3-4 साल पहले बन जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाने के पश्चात तीसरे मोर्चे बनाने की छोटी-मोटी सुगबुहाट जरूर होती गई, कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में नया राजनीतिक दल खड़ा किया जाए, जिससे क्षेत्रीय संतुलन बना रहें, आज के समय में हिमाचल की स्थिति यह हैं कि पूरा प्रदेश राजनीतिक रूप से दो भागों में विभाजित हैं।

आज तक इन दो राजनीतिक पार्टियों के सिवाय तीसरा दल उभरने में कामयाब नहीं हुआ हैं। हिमाचल प्रदेश में यदि किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल को 5-7 सीटों की आवश्यकता हो और इतनी सीटें लाने में तीसरा मोर्चा कामयाब हो जाता हैं तो उस स्थिति में उनका वर्चस्व जरूर बढ़ेगा, लेकिन यह असंभव व कठिन प्रतीत होता हैं।

क्योंकि जब भी कभी नया दल बनाया जाता हैं और नए दल में लोग संगठित होते हैं उसके लिए दो बातों की अहम भूमिका होती हैं। पहला आप किस दृष्टिकोण को लेकर नए राजनीतिक दल का गठन करना चाहते हैं और दूसरा आपका न्यूनतम कार्यक्रम क्या हैं? और आप अपना न्यूनतम कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच कब जाएगे, जिसके लिए पर्याप्त समय की भी आवश्यकता रहती हैं। आपको पंचायत स्तर पर जाना होगा और लोगों को अपना कार्यक्रम अच्छे से समझना होगा, कि हमारा कार्यक्रम इन दो पार्टियों से अलग हैं हम जनता के लिए कुछ नया करना चाहते हैं इसलिए आप जो कुछ नया करना चाहते हैं उसके लिए आप कैसे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करेगे, क्योंकि जनता भी राजनीतिक रूप से दो भागों में विभाजित हैं। एक तरह सशक्त भारतीय जनता पार्टी हैं और दुसरी तरह सत्ता में अभी काँग्रेस पार्टी हैं अब इन दोनों के बीच संग्राम में आप कितना बेहतर कर पाओगे यह सिर्फ़ समय ही तय करेगा। क्योंकि राजनीति में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में तीसरे विकल्प की चर्चा आकर्षक जरूर हैं, लेकिन इतिहास के आकड़ें यह बताते हैं कि इसकी राह बेहद कठिन रहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय काँग्रेस पार्टी का मजबूत ढांचा, जनाधार व वर्षों के अनुभव ने तीसरे विकल्प के लिए जगह सीमित रही हैं। फ़िर भी लोकतंत्र की यह खासियत हैं कि इसमें कोई संभवना पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं, यदि भविष्य में कोई नया नेतृत्व, नई सोच और मजबूत संगठन उभरता हैं, तो हिमाचल की राजनीति में बदलाव संभव हैं।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

माओवादी मुक्ति से शांति एवं संतुलन की नई संभावनाएं

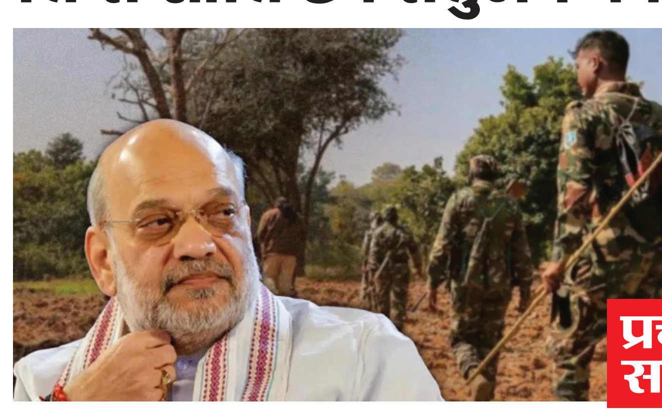

-: ललित गर्गः-

भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और लोकतांत्रिक राष्ट्र के सामने आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हमेशा से बहुआयामी रही हैं। इन चुनौतियों में नक्सलवाद या माओवादी हिंसा एक ऐसी समस्या रही, जिसने दशकों तक देश की आंतरिक शांति, विकास और सुशासन को गंभीर रूप से प्रभावित किया। विशेषकर छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार और आंध्र प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों ने न केवल विकास को अवरुद्ध किया, बल्कि हजारों निर्दोष नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की जान भी ली। लेकिन आज जब बस्तर जैसे माओवादी गढ़ से 25 लाख के इनामी सरगना पापा राव का अपने साथियों सहित आत्मसमर्पण करना एक निर्णायक मोड़ के रूप में सामने आया है, तब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत माओवादी मुक्ति की ऐतिहासिक दहलीज पर खड़ा है। नक्सलवाद की जड़ें सामाजिक-आर्थिक असमानता, उपेक्षा और शोषण में रही हैं, लेकिन समय के साथ यह आंदोलन अपने मूल उद्देश्यों से भटककर एक हिंसक और विध्वंसकारी विचारधारा में बदल गया। माओवादी संगठन न केवल विकास कार्यों में बाधा डालते रहे, बल्कि उन्होंने स्थानीय लोगों को भय और हिंसा के माध्यम से नियंत्रित किया। स्कूल, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र जैसे बुनियादी ढांचे को नष्ट करना उनकी रणनीति का हिस्सा बन गया था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह आंदोलन अब जनहित का नहीं, बल्कि सत्ता और नियंत्रण का माध्यम बन चुका है।

भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद/माओवाद से मुक्त करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह अब लगभग अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचता दिखाई दे रहा है। पिछले एक दशक में 10,000 से अधिक माओवादियों के आत्मसमर्पण, सुरक्षा बलों की आक्रामक एवं रणनीतिक कार्रवाई तथा प्रभावित क्षेत्रों में तेज़ी से हुए विकास कार्यों ने माओवादी आंदोलन की जड़ों को कमजोर कर दिया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में माओवादी हिंसा की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। विशेष रूप से शीर्ष नेतृत्व के आत्मसमर्पण, जैसे दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्यों के सरेंडर ने संगठन को नेतृत्वहीन कर दिया, जिससे माओवादी संरचना भीतर से कमजोर पड़ गई। इस सफलता के पीछे सरकार की बहुआयामी रणनीति रही, जिसमें केवल सैन्य-पुलिस कार्रवाई ही नहीं, बल्कि विकास, पुनर्वास और प्रशासनिक पहुंच को भी समान महत्व दिया गया। रेड कॉरिडोर क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण, मोबाइल टावरों के माध्यम से 4जी नेटवर्क का विस्तार, स्कूलों और आईटीआई संस्थानों की स्थापना ने इन क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ा। वहीं 'फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों' की रणनीति के माध्यम से सुरक्षा बलों ने माओवादियों के गढ़ों में घुसकर निर्णायक कार्रवाई की। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए पुनर्वास नीति के तहत आर्थिक सहायता, रोजगार और समाज में पुनर्स्थापना की व्यवस्था ने भी माओवादी कैडर को हथियार छोड़ने के लिए प्रेरित किया। यह समन्वित रणनीति, दूरदर्शिता और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिणाम है कि देश आज नक्सलवाद के अंत के ऐतिहासिक चरण के निकट खड़ा दिखाई दे रहा है।

निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी और दृढ़ रणनीति अपनाई। गृहमंत्री अमित शाह की सूझबूझ और स्पष्ट दृष्टिकोण ने इस अभियान को एक नई दिशा दी। सरकार ने एक ओर जहां सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण और संसाधनों से सशक्त किया, वहीं दूसरी ओर विकास योजनाओं को भी गति दी। 'सुरक्षा और विकास' के इस दोहरे दृष्टिकोण ने माओवादी प्रभाव वाले क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखी। पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षाबलों द्वारा चलाए गए सघन अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को गहराई से कमजोर किया है। बस्तर, जो कभी माओवादियों का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां आज आत्मसमर्पण की घटनाएं बढ़ रही हैं। पापा राव जैसे शीर्ष माओवादी नेता का आत्मसमर्पण इस बात का संकेत है कि माओवादी संगठन अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह केवल एक व्यक्ति का आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि एक विचारधारा के पतन का प्रतीक है।

माओवादी मुक्ति का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि देश के उन क्षेत्रों में शांति और स्थिरता स्थापित होगी, जो लंबे समय से हिंसा की चपेट में रहे हैं। जब बंदूकें खामोश होंगी, तब विकास की आवाज बुलंद होगी। सड़कें बनेंगी, स्कूल खुलेंगे, अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ेंगी और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों के जीवन में सुरक्षा और विश्वास का संचार होगा। आदिवासी और ग्रामीण समुदाय, जो अब तक भय और असुरक्षा में जी रहे थे, वे अब अपने अधिकारों और अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही, माओवादी हिंसा के समाप्त होने से भारत की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। जब देश के भीतर शांति होगी, तब ही बाहरी खतरों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है। नक्सलवाद जैसी समस्याएं अक्सर विदेशी शक्तियों और असामाजिक तत्वों के लिए भी अवसर प्रदान करती हैं, जिन्हें समाप्त करना राष्ट्रीय हित में अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से माओवादी मुक्ति न केवल आंतरिक, बल्कि सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।

आदर्श शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए कानून का शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास की समान पहुंच आवश्यक होती है। माओवादी प्रभाव वाले क्षेत्रों में इन सभी तत्वों का अभाव था। वहां प्रशासन की पहुंच सीमित थी और लोकतांत्रिक संस्थाएं प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पा रही थीं। लेकिन अब जब माओवादी प्रभाव घट रहा है, तब सरकार के लिए यह अवसर है कि वह इन क्षेत्रों में सुशासन की मजबूत नींव रखे। पंचायतों को सशक्त किया जाए, स्थानीय नेतृत्व को प्रोत्साहित किया जाए और जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। यह भी आवश्यक है कि माओवादी विचारधारा के प्रभाव को केवल सुरक्षा उपायों से ही नहीं, बल्कि वैचारिक स्तर पर भी चुनौती दी जाए। शिक्षा, जागरूकता और संवाद के माध्यम से लोगों को यह समझाना होगा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। लोकतंत्र में परिवर्तन का मार्ग शांतिपूर्ण और संवैधानिक होता है। इस दिशा में समाज, सरकार और नागरिक संगठनों को मिलकर प्रयास करना होगा। माओवादी मुक्ति के इस दौर में यह भी ध्यान रखना होगा कि जिन कारणों से यह समस्या उत्पन्न हुई थी, वे दोबारा न उभरें। सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और विकास की समावेशी नीति को प्राथमिकता देना आवश्यक है। आदिवासी क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, पहचान और अधिकारों का सम्मान करते हुए विकास की योजनाएं लागू की जानी चाहिए। केवल भौतिक विकास ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जिस दृढ़ता और दूरदर्शिता के साथ माओवादी समस्या का समाधान किया जा रहा है, वह न केवल वर्तमान के लिए, बल्कि भविष्य के लिए भी एक मार्गदर्शक है। यह दिखाता है कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति मजबूत हो, रणनीति स्पष्ट हो और कार्यान्वयन प्रभावी हो, तो कोई भी समस्या असाध्य नहीं है। निश्चिततौर पर माओवादी मुक्ति केवल एक सुरक्षा उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र, विकास और सुशासन की जीत है। यह उस विश्वास का प्रतीक है कि भारत अपने आंतरिक संघर्षों को शांतिपूर्ण और निर्णायक ढंग से सुलझाने में सक्षम है। अब समय है कि इस उपलब्धि को स्थायी बनाया जाए और देश के हर कोने में शांति, समृद्धि और संतुलन का वातावरण स्थापित किया जाए। जब हर नागरिक सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त महसूस करेगा, तभी सच्चे अर्थों में एक आदर्श शासन व्यवस्था का निर्माण संभव हो सकेगा।

प्रेषक
(ललित गर्ग)
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
ई-253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट 25 आई॰ पी॰ एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092
मो. 9811051133

अप्रैल में कब है वरूथिनी एकादशी व मोहिनी एकादशी, नोट करें तिथि और मुहूर्त

हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। धार्मिक मान्यता के अनुसार, विधिपूर्वक एकादशी व्रत करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है।

अप्रैल में कब कौन-सी एकादशी है?

वैदिक पंचांग के अनुसार, 13 अप्रैल को वरूथिनी एकादशी (Varuthini Ekadashi 2026) और 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी (Mohini Ekadashi 2026) व्रत किया जाएगा।

वरूथिनी एकादशी 2026 डेट और शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि देर रात 01 बजकर 16 मिनट पर शुरू होगी। वहीं, इसका समापन 14 अप्रैल को देर रात 01 बजकर 08 मिनट पर होगा। ऐसे में वरूथिनी एकादशी व्रत 13 अप्रैल को किया जाएगा।

वरूथिनी एकादशी 2026 व्रत पारण टाइम

इस एकादशी व्रत का पारण का समय 14 अप्रैल को सुबह 06 बजकर 54 मिनट से 08 बजकर 31 मिनट तक है।

मोहिनी एकादशी 2026 डेट और शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 26 अप्रैल को शाम 06 बजकर 06 मिनट पर होगी। वहीं, समापन 27 अप्रैल को शाम 06 बजकर 15 मिनट पर होगा। ऐसे में मोहिनी एकादशी व्रत 27 अप्रैल को किया जाएगा।

मोहिनी एकादशी 2026 व्रत पारण टाइम

मोहिनी एकादशी व्रत का पारण करने का समय सुबह 05 बजकर 43 मिनट से 08 बजकर 21 मिनट तक है।

इन बातों का रखें ध्यान

एकादशी व्रत के दिन सात्विक भोजन का सेवन करें।
किसी से वाद-विवाद न करें।
काले रंग के कपड़े धारण न करें।
घर और मंदिर में साफ-सफाई का ध्यान रखें।
व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर करें।
अन्न-धन समेत आदि चीजों का दान करें।
तुलसी की पूजा-अर्चना करें।
व्रत कथा का पाठ करें।
भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें।

आज मनाई जाएगी महावीर जयंती, यहां पढ़ें भगवान महावीर के उपदेश

31 मार्च यानी मंगलवार को महावीर जयंती मनाई जाएगी। भगवान महावीर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला महावीर जयंती जैन धर्म का सबसे प्रमुख त्यौहार है। यह पर्व सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश देता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस दिन को बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है। महावीर जी का जन्म ईसा पूर्व 599 में, वैशाली (वर्तमान बिहार) के कुंडलपुर में एक क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। भगवान महावीर ने 30 साल की आयु में संन्यास लेने के बाद अपने जीवन काल में कई ऐसी शिक्षाएं दी हैं जो आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। तो आइए जानते हैं भगवान महावीर उपदेश के बारे में।

पंच महाव्रत

अहिंसा
सत्य
अस्तेय
ब्रह्मचर्य
अपरिग्रह
अहिंसा

अहिंसा महावीर जी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। भगवान महावीर के अनुसार, मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न देना ही सबसे बड़ा धर्म है। 'जियो और जीने दो' उनका सबसे प्रसिद्ध नारा है।

सत्य

हमेशा सत्य बोलें। सत्य बोलने के लिए मन का शांत और क्रोधरहित होना आवश्यक है। महावीर जी ने आजीवन लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उनका मानना था कि सच्चे विचार और अच्छी वाणी के साथ जीवन जीने से हर लक्ष्य व्यक्ति प्राप्त कर सकता है।

अस्तेय

किसी दूसरे की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के ग्रहण न करना। लालच का त्याग करना। यह महावीर जी का प्रमुख संदेशों में से एक है। भगवान महावीर के अनुसार, जो अपना नहीं है उसे कभी भी किसी से लेना नहीं चाहिए। ईमानदारी से जीवन जीने से और जो अपने पास मौजूद है उससे संतुष्ट रहने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है।

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और वासनाओं से दूर रहना। महावीर जी ने गृहस्थों और साधुओं दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा दी है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति संयम में रहता है और जीवन में सही मार्ग पर अग्रसर हो पाता है।

अपरिग्रह

महावीर जी कहते हैं कि व्यक्ति को अनावश्यक वस्तुओं, धन या संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। भौतिक चीजों के प्रति मोह ही दुःख का कारण बनता है। अपरिग्रह यानि किसी भी इच्छा में, संबंध में या किसी वस्तु से आसक्ति न रखना। जो व्यक्ति इन इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते है उसके लिए फिर कुछ भी असंभव नहीं रह जाता।

भगवान महावीर के उपदेश

हर जीवित प्राणी के प्रति अपने मन में दया भाव रखना ही अहिंसा होता है। घृणा की भावना से हम स्वयं का विनाश करते हैं और यह दूसरों के लिए भी कष्टकारी हो सकती है।

महावीर स्वामी ने कहा था, मनुष्य के दुखी होने का कारण उसकी खुद की गलतियां हैं। जो मनुष्य अपनी गलतियों पर काबू पा लेता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है।

मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। हमें हमेशा जियो और जीने दो संदेश को मानना चाहिए।

असल में शत्रु हमारे अंदर ही रहते हैं। ये शत्रु- द्वेष, लालच, घमंड, क्रोध और नफरत है। खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से उत्तम होता है।

भगवान का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। हर कोई सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास कर के देवत्त्व प्राप्त कर सकता है।

प्रत्येक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ और आनंदमय है। आनंद बाहर से नहीं आता।

हनुमान जयंती की रात करें बजरंग बाण का पाठ, पढ़ें सही विधि, न करें ये काम

चैत्र महीने की पूर्णिमा संकटमोचन हनुमान जी के जन्मोत्सव का प्रतीक है। हनुमान जयंती की रात को बेहद सिद्ध और प्रभावशाली माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस विशेष रात्रि को अगर पूरी श्रद्धा के साथ बजरंग बाण का पाठ किया जाए, तो बड़े से बड़ा संकट दूर किया जा सकता है।

आइए इससे जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं।

बजरंग बाण पाठ की सही विधि

हनुमान जयंती की रात एक शांत स्थान पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें।

लाल रंग के आसन पर बैठें और हो पाए तो लाल वस्त्र धारण करें।

चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उसमें दो लौंग डाल दें।

हनुमान जी को बेसन के लड्डू या बूंदी का भोग लगाएं।

पाठ शुरू करने से पहले हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना बोलें और भगवान श्री राम का ध्यान करें।

कम से कम 1, 3, 5 या 7 बार बजरंग बाण का पाठ करें।

अंत में आरती करें।

इन नियमों का रखें ध्यान

हनुमान जयंती के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें।

मांस-मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें और मन में किसी के प्रति बुरा भाव न रखें।

बजरंग बाण के शब्दों का उच्चारण साफ करें।

॥श्री बजरंग बाण पाठ॥

॥ दोहा ॥

निश्चय प्रेम प्रतीति ते, बिनय करैं सनमान ।
तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करैं हनुमान॥

॥ **चौपाई** ॥

जय हनुमंत संत हितकारी । सुन लीजै प्रभु अरज हमारी ॥
जन के काज बिलंब न कीजै । आतुर दौरि महा सुख दीजै ॥
जैसे कूदि सिंधु महिपारा । सुरसा बदन पैठि बिस्तारा ॥
आगे जाय लंकिनी रोका । मारेहु लात गई सुरलोका ॥
जाय बिभीषन को सुख दीन्हा । सीता निरखि परमपद लीन्हा ॥
बाग उजारि सिंधु महँ बोरा । अति आतुर जमकातर तोरा ॥
अक्षय कुमार मारि संहारा । लूम लपेटि लंक को जारा ॥
लाह समान लंक जरि गई । जय जय धुनि सुरपुर नभ भई ॥
अब बिलंब केहि कारन स्वामी । कृपा करहु उर अन्तर्यामी ॥
जय जय लखन प्राण के दाता । आतुर ह्वै दुःख करहु निपाता ॥
जै गिरिधर जै जै सुख सागर । सुर-समूह-समरथ भटनागर ॥
ॐ हनु हनु हनु हनुमंत हठीले । बैरिहि मारु बज्र की कीले ॥
गदा बज्र लै बैरिहिं मारो। महाराज प्रभु दास उबारो॥
ॐ कार हुंकार महाप्रभु धावो । बज्र गदा हनु विलम्ब न लावो ।
ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं हनुमंत कपीशा । ॐ हुं हुं हुं हनु अरि उर शीशा ॥
सत्य होहु हरि शपथ पायके । राम दूत धरु मारु जाय के ॥
जय जय जय हनुमंत अगाधा । दुःख पावत जन केहि अपराधा ॥
पूजा जप तप नेम अचारा । नहिं जानत हौं दास तुम्हारा ॥
वन उपवन मग गिरि गृह माहीं । तुम्हरे बल हम डरपत नाहीं ॥
पांय परौं कर जोरि मनावौं । येहि अवसर अब केहि गोहरावौं ॥
जय अंजनि कुमार बलवंता । शंकर सुवन वीर हनुमंता ॥
बदन कराल काल कुल घालक । राम सहाय सदा प्रतिपालक ॥
भूत, प्रेत, पिशाच निशाचर । अग्नि बेताल काल मारी मर ॥
इन्हें मारु, तोहि शपथ राम की । राखउ नाथ मरजाद नाम की ॥
जनकसुता हरि दास कहावो । ताकी शपथ बिलंब न लावो ॥
जै जै जै धुनि होत अकासा । सुमिरत होय दुसह दुःख नाशा ॥
चरण शरण कर जोरि मनावौं । यहि अवसर अब केहि गोहरावौं ॥
उठु, उठु, चलु, तोहि राम दुहाई । पाँय परौं, कर जोरि मनाई ॥
ॐ चं चं चं चं चपल चलंता । ॐ हनु हनु हनु हनु हनुमंता ॥
ॐ हं हं हाँक देत कपि चंचल । ॐ सं सं सहमि पराने खल दल ॥
अपने जन को तुरत उबारो । सुमिरत होय आनंद हमरो ॥
यह बजरंग बाण जेहि मारै । ताहि कहो फिरि कौन उबारै ॥
पाठ करै बजरंग बाण की । हनुमत रक्षा करै प्रान की ॥
यह बजरंग बाण जो जापै । ताते भूत-प्रेत सब कापैं ॥
धूप देय जो जपै हमेशा । ताके तन नहिं रहै कलेशा ॥

न्यूज ब्रीफ..

जानकारी नहीं है तो जानकारी जुटाए और कार्रवाई करें मुख्यमंत्रीः जयराम ठाकुर

शिमला . मुख्य सचिव पर लग रहे आरोपों से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सीएम कहते हैं कि अभी उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री समझ लें कि अब जानकारी नहीं होने से काम नहीं चलेगा? अगर जानकारी नहीं है तो जिम्मेदार राजस्व के अधिकारियों को बुलाकर जांच रिपोर्ट समझे और जरूरी एक्शन लें। अगर जो आरोप लगा रहे हैं वह आरोप सही है तो यह स्थिति बहुत खतरनाक है। हिमाचल के लिए खतरे की घंटी है। हमने पहले दिन से ही कहा कि मुख्यमंत्री कुछ भ्रष्टाचारियों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। कांग्रेस को फंडिंग करने के लिए उन्होंने जिन अधिकारियों को लगाया था अब उन अधिकारियों से कुछ कहने की मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हो रही है। खुलेआम लूट मची हुई है। भ्रष्टाचार चरम पर है। जिस अधिकारी के हाथ जो लग रहा है वह उठा ले रहा है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री निपटने–निपटाने की जिस राजनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। उससे प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। अपने कई बड़े मंत्रियों को वह निपटा भी चुके हैं। जिन भ्रष्ट अधिकारियों के कहने पर वह चल रहे हैं, वे अधिकारी उन्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। बड़े –बड़े नेताओं को हमने लड़ाई लड़ते देखा, लेकिन अंतत वह सभी एक बंद कमरे के किसी कोने में मिलकर गले मिलते हैं और मामले निपटाते हैं। मुख्यमंत्री को बरगलाने वाले वे अधिकारी भी समझ लें की समय आने पर उनकी कारगुज़ारियों का हिसाब होगा। भाजपा कांग्रेस के सुक्खू सरकार की ओछी हरकतों से डरने वाली नहीं है। हम सरकार की हर साजिश का सामना करेंगे।

हिमाचल सरकार के फैसलों के विरोध में सभी प्रमुख 33 एंट्री प्वाइंट को बंद करने की योजना

सुमन डोगरा, बिलासपुर . हिमाचल प्रदेश सरकार के हालिया फैसलों के विरोध में पंजाब-हिमाचल सीमा पर बड़ा आंदोलन खड़ा होता दिख रहा है। पंजाब मोर्चा ने ऐलान किया है कि 31 मार्च की आधी रात से हिमाचल में प्रवेश करने वाले मार्गों को बंद कर चक्का जाम किया जाएगा। पत्रकारों को जानकारी देते हुए पंजाब मोर्चा के संयोजक गौरव राणा ने बताया कि हिमाचल सरकार द्वारा टोल प्लाजा और एंट्री टैक्स में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ यह कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का सबसे अधिक असर पंजाब सीमा से जुड़े क्षेत्रों के लोगों पर पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें रोज़मर्रा के कामकाज के लिए हिमाचल प्रदेश में बार-बार आना-जाना पड़ता है। गौरव राणा ने कहा कि टैक्स बढ़ने से स्थानीय लोगों की जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी के विरोध में 31 मार्च की मध्यरात्रि से हिमाचल-पंजाब सीमा पर स्थित सभी प्रमुख 33 एंट्री प्वाइंट को बंद करने की योजना बनाई गई है। उन्होंने आगे बताया कि इस आंदोलन में विभिन्न संगठनों का समर्थन मिल रहा है। किसान यूनियन, टैक्सी यूनियन और ट्रक यूनियन सहित कई जत्थेबंदियां इस विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लेंगी। सीमा पर चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। पंजाब मोर्चा के संयोजक ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने टोल और एंट्री टैक्स में की गई वृद्धि को वापस नहीं लिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस संभावित बंद और चक्का जाम के चलते आने वाले दिनों में हिमाचल-पंजाब सीमा पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना की समीक्षा बैठक आयोजित

कुल्लू . पीएम पोषण शक्ति निर्माण (मिड डे मील) योजना की जिला संचालन एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सुनील ठाकुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी कुंदन लाल, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉ. सुरेश कुमार सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक का संचालन उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सुनील कुमार ने किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के 7 शिक्षा खंडों के अंतर्गत 1006 प्री-प्राइमरी, प्राइमरी तथा अपर प्राइमरी विद्यालयों में कुल 35,118 विद्यार्थियों को मिड-डे मील प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी 1006 विद्यालयों में किचन गार्डन भी स्थापित किए गए हैं। उपायुक्त ने अधिकारियों को बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए सभी विद्यालयों में निर्धारित मेनू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिला कुल्लू को इस योजना के अंतर्गत 7 करोड़ 49 लाख 64 हजार 452 रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

उन्होंने योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के साथ साथ भोजन की गुणवत्ता एवं पोषण स्तर की निगरानी, निर्धारित दिशा-निर्देशों के पालन, स्वच्छता एवं पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण तथा बजट उपयोग के लिये भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये। उन्होंने विद्यालयों के किचन की स्वच्छता, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता तथा भोजन की नियमित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

एपीजी शिमला विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर अकादमिक संगोष्ठी आयोजित

प्रचण्ड समय . शिमला

एपीजी शिमला विश्वविद्यालय में "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का व्यावहारिक क्रियान्वयनः उच्च शिक्षा में चुनौतियाँ एवं अवसर" विषय पर एक दिवसीय अकादमिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सोलन तथा राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान के सहयोग से आयोजित हुई।

संगोष्ठी का समन्वयन डॉ. मनींदर कौर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से आए शिक्षाविदों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया। संगोष्ठी का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों एवं संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा करना था।

कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रो. (डॉ.) आर. एस. चौहान के उद्घाटन संबोधन से हुआ। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025–26 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया है। उन्होंने इस नीति को भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तनकारी पहल बताते हुए कहा कि यह बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास और लचीले पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को उद्योगोन्मुख बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. (डॉ.) आर. एल. शर्मा, डीन अकादमिक प्रो. (डॉ.) आनंद मोहन, डीन इंजीनियरिंग प्रो. (डॉ.) अंकित ठाकुर तथा प्रो-चांसलर प्रो. रमेश चौहान उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में डॉ. राकेश शर्मा, डॉ. विनोद कुमार, डॉ. मनीषा कोहली तथा डॉ. दीपक गुप्ता शामिल रहे।

रजिस्ट्रार प्रो. (डॉ.) आर. एल. शर्मा ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों जैसे पाठ्यक्रम पुनर्गठन, संकाय प्रशिक्षण एवं अवसंरचना विकास पर प्रकाश डाला। डीन अकादमिक प्रो. (डॉ.) आनंद मोहन ने नीति के उद्देश्यों और इसकी दूरदर्शी सोच पर विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किया।

संगोष्ठी के अंतर्गत आयोजित पैनल चर्चा में डॉ. राकेश शर्मा, प्रो. (डॉ.) आर. एल. शर्मा, डॉ. मनीषा कोहली एवं प्रो. (डॉ.) आनंद मोहन ने भाग लिया।

पैनल में संस्थागत तैयारियों, नवाचार की संभावनाओं एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के समक्ष आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। वक्ताओं ने संकाय विकास, अकादमिक लचीलापन, छात्र-केंद्रित शिक्षा एवं उद्योग-शिक्षा समन्वय को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया।

संगोष्ठी में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिनमें राजकीय महाविद्यालय सोलन, राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान, राजकीय महाविद्यालय संजौली तथा एपीजी शिमला विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एवं शिक्षक शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के बीच विचारों एवं अनुभवों का सार्थक आदान-प्रदान हुआ।

कार्यक्रम का समापन वैलेडिक्टरी सत्र एवं प्रमाण-पत्र वितरण के साथ हुआ। इस अवसर पर वक्ताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए संस्थागत समन्वय, रणनीतिक योजना एवं सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

कुल्लू स्टूडेंट्स एसोसिएशन समर हिल शिमला

प्रचण्ड समय . कुल्लू

स्युडेंट्स एसोसिएशन शिमला द्वारा आज कुल्लू से सबंधित प्रसिद्ध साहित्यकार, कुलवी संस्कृती के पुरोधा, लोक लेखक स्वर्गीय डा विद्या चंद ठाकुर की जयंती मनाई गयी !इस अवसर पर स्वर्गीय ठाकुर जी के कार्यों को याद कर उन्हें नमन किया गया !इस अवसर पर कुल्लू पीपुल्स एसोसिएशन शिमला के अध्यक्ष अनुराग पाराशर ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया !उन्होंने अपने सम्बोधन मे डा विद्या चद ठाकुर जी को याद करते हुए कहा की डा ठाकुर ने जहाँ कुलवी संस्कृति को बढ़ावा दिया वहीं जहाँ जहाँ भी जिला भाषा अधिकारी रहे वहा भी वहाँ की संस्कृति को बढ़ावा दिया! मांडव प्रभा नामक उनकी मंडी के मंदिरो बारे लिखी उनकी पुस्तक एक दस्तावेज इसका सपष्ट उदाहरण है !पाराशर ने बताया की उनकी सादगी, उनके विचार आज प्रासंगिक लग रहे हैं! इसीलिए इस बार डा ठाकुर की जयंती मोटिवेशनल विषय पर विशेष कर विद्यार्थियों के लिये आयोजित की गई और इसके अंतर्गत ही कुल्लू व शिमला मे समारोह आयोज़ित किये गये !कुल्लू का समारोह खोड़ा आगे मे आयोज़ित किया गया! इस अवसर पर कुल्लू स्टूडेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी सहित काफ़ी संख्या मे सदस्य उपस्थित रहे !कुल्लू स्टूडेंट्स एसोसिएशन की उप प्रधान कुमारी डिम्पल ठाकुर ने भी फूल पुष्प चढ़ा कर अपमे भाव प्रकट किये !महासचिव आशीष ठाकुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया !गौरतलब है कि डा विद्या चंद ठाकुर लोक साहित्य लोक कला को अर्पित मूल रूप से एक भाषा अधिकारी थे ज़ो सहायक निदेशक भाषा व संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार से सेवनिवृत हुए थे !उनके योगदान को आज कुल्लू व शिमला मे याद किया गया !

अंबेडकर चौक शिमला में प्रतिमा हटाने की आशंका दूर, सौंदर्यकरण कार्य जारी

प्रचण्ड समय . शिमला

आज नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री जी से शिमला शहरी में सभी बहुजन समाज के विभिन संगठनों सभाओं अंबेडकरवादी संगठनों उनके पदाधिकारियों सदस्यों अनुयियों ने मुलाकात की और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर चौक चौड़ा मैदान शिमला में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर जो संशय अंबेडकर प्रतिमा बहां से हटाने का था, उसको दूर किया गया। आयुक्त से मुलाकात करने बालों में साथ रहे, कर्म चंद भाटिया, सुशील कुमार बौद्व विट्टू माना,रजनी सिंह,नागेश बाल्मिकी,अशोक घारू,रवि दलित,विट्टू घारू,नरेश गांधी,विक्की शुभ,विनोद गहलोत,मंडी राम,प्रितपाल मट्टू,अमित भाटिया,पूर्व मंत्री रुप दास कश्यप,सोहन लाल कुमार।

#आयुक्त साहब ने आश्वस्त किया कि वहां से पुरानी प्रतिमा अंबेडकर जी की नहीं हटाई जाएगी साथ में सौंदर्यकर्ण किया जा रहा है और साथ में सभी ने भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को रिज पर स्थापित करने की भी मांग की उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि सरकार से हम इस बात को उठाएंगे और सरकार के ध्यानअर्थ है आपके मांग के पत्र हमारे नोटिस कारवाई में हैं।

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भेंट की

प्रचण्ड समय . शिमला

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से शिष्टाचार भेंट की। हिमाचल के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण करने के उपरान्त कविन्द्र गुप्ता की यह राष्ट्रपति के साथ पहली भेंट है। इस अवसर पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति को हिमाचल प्रदेश की स्थिति से अवगत करवाया तथा राज्य में कार्यन्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। राष्ट्रपति ने राज्यपाल को शुभकामनाएं देते हुए हिमाचल प्रदेश के लोगों के विकास, सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना की।

मोदी सरकार ने हिमाचल को दी 3,920 करोड़ की ऐतिहासिक सौगात — पहाड़ी राज्यों के विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण : बिंदल

प्रचण्ड समय . शिमला

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने केंद्र सरकार द्वारा "प्राइड ऑफ हिल्सः स्पेशल डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर हिल स्टेट्स" (SASCI 2026-27) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 3,920 करोड़ की विशेष सहायता प्रदान करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया है।

डॉ. बिंदल ने कहा कि यह सहायता केवल एक वित्तीय पैकेज नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष स्नेह और संवेदनशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों को भौगोलिक कठिनाइयों, सीमित संसाधनों, कम जनसंख्या घनत्व और सीमित राजस्व स्रोतों के कारण विकास में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसे समझते हुए केंद्र सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कुल 25,000 करोड़ के विशेष प्रावधान में हिमाचल प्रदेश को 3,920 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह राशि राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास, सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, जलापूर्ति और अन्य विकासात्मक कार्यों को नई गति प्रदान करेगी।

डॉ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार जहां एक ओर प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश पर बढ़ता हुआ कर्ज चिंता का विषय है, ऐसे समय में केंद्र की यह सहायता प्रदेश को राहत प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का यह कदम "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" की भावना को साकार करता है। पहाड़ी राज्यों के समग्र विकास के लिए यह योजना मील का पत्थर साबित होगी।

डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा हिमाचल प्रदेश का विशेष ध्यान रखा है और समय-समय पर प्रदेश को आर्थिक सहायता, विशेष पैकेज और विकास योजनाएं प्रदान कर यह साबित किया है कि केंद्र सरकार हिमाचल के साथ मजबूती से खड़ी है।

अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और यह सहायता प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला बनेगी।

अगर आप रात में 9 से 10 के बीच खाना खाते हैं तो इससे आपके शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है?

रात में 9 से 10 बजे के बीच खाना खाना आज की व्यस्त जीवनशैली में आम बात बन गई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है? देर से खाने की आदत न सिर्फ आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करती है, बल्कि यह आपकी नींद, वजन और मेटाबॉलिज्म पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती है। खासतौर पर जब शरीर आराम की तैयारी कर रहा होता है, उस समय भारी भोजन करना कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि देर रात का खाना आपकी सेहत के लिए कितना सही या नुकसानदायक है

रात में लेट खाना खाने से क्या होता है?

देर रात खाना खाने से मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। यह शरीर के प्राकृतिक सर्केडियन चक्र (24-घंटे की जैविक घड़ी) में व्यवधान के कारण होता है, जो रात में कैलोरी बर्न करने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसलिए खाया गया भोजन ऊर्जा के बजाय चर्बी के रूप में जमा हो जाता है, जिससे कई गंभीर बीमारियों किस समस्या बढ़ जाती है।

रात में देर से खाने के प्रभाव

वजन बढ़ना:

जब आप देर रात खाते हैं, तो शरीर भोजन को ठीक से पचा नहीं पाता, जिससे कैलोरी बर्न होने के बजाय वसा में बदल जाती है और वजन तेजी से बढ़ सकता है।

पाचन संबंधी समस्याएँ:

रात में लेट खाना खाने से पाचन तंत्र धीमा हो जाता है, जिससे भोजन पूरी तरह नहीं पचता और एसिडिटी, सीने में जलन और अपच का कारण बनता है।

नींद में खलल:

भरा हुआ पेट लेकर सोने से नींद की गुणवत्ता खराब होती है, जिससे नींद पूरी नहीं होती और थकान बनी रहती है।

हृदय और शुगर का खतरा:

देर रात का भोजन ब्लड शुगर लेवल को अचानक बढ़ा सकता है और हृदय रोग का खतरा भी बढ़ा सकता है।

शोध बताते हैं कि रात में देर से खाना खाने से चयापचय में बाधा आती है, जिससे इंसुलिन प्रतिरोध, मोटापा और टाइप 2 मधुमेह का जोखिम बढ़ जाता है, जो हृदय स्वास्थ्य को कमजोर करता है

कहीं आप भी तो नहीं खा रहे मिलावटी घी? FSSAI के बताए इस सिंपल टेस्ट से 5 मिनट में करें चेक

इन दिनों बाजार में मिलावटखोरी खुलेआम जारी है। दूध से लेकर आटे तक, आजकल लगभग खाने-पीने की हर चीज में मिलावट की जा रही है।

इसी तरह मार्केट में मिलावटी घी भी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है।

घी कई मायनों में हमारे लिए फायदेमंद होता है और इसलिए लोग हेल्दी रहने के लिए इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं।

हालांकि, यह चिंता की बात है कि बाजार में मिलने वाले घी में अब वनस्पति या हाइड्रोजनीकृत फैट मिलाया जाता है, जो सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।

ऐसे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स एक ऐसा तरीका शेयर किया है, जिसकी मदद से आप 5 मिनट में असली और नकली घी की पहचान कर सकते हैं।

आइए जानते हैं इसके बारे में-

कैसे करें असली और नकली घी की पहचान

आपको क्या चाहिए

1 मिलीलीटर पिघला हुआ घी

1 मिलीलीटर कंसन्ट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड (एचसीएल)

आधा चम्मच चीनी

एक टेस्ट ट्यूब या छोटा कांच का बर्तन।

घी टेस्ट करने का तरीका

सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में 1 मिलीलीटर पिघला हुआ घी लें।

फिर उसमें 1 मिलीलीटर कंसन्ट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएं।

इसके बाद आधा चम्मच चीनी मिलाएं। मिश्रण को लगभग 2 मिनट तक जोर से हिलाएं। मिश्रण को जमने दें और परतों में अलग होने दें।

शुद्ध और मिलावटी घी की पहचान

शुद्ध (बिना मिलावट वाला) घी: रंग में कोई बदलाव नहीं दिखेगा।

मिलावटी घी (वनस्पति या हाइड्रोजनीकृत फैट वाला): एसिडिक लेयर गहरे लाल या गुलाबी रंग की हो जाती है। रंग यब बदलाव मिलावट का साफ संकेत है।

कैसे काम करता है ये टेस्ट

यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत सिंपल की साइंस है, जिसकी मदद से इस आप घी की पहचान कर सकते हैं। इसके पीछे काफी दिलचस्प और बेसिक केमिकल साइंस है-

हाइड्रोक्लोरिक एसिड शुगर यानी चीनी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। ये शुगर, डिहाइड्रेट होने पर, फरफ्यूरल नाम का कंपाउंड बनाती हैं।

फरफ्यूरल वनस्पति या तिल के तेल में मौजूद कुछ पदार्थों के साथ रिएक्ट करते हैं। यह रिएक्शन लाल या गुलाबी रंग उत्पन्न करता है, जो मिलावट का संकेत है।

शुद्ध घी में ये कंपाउंड मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

घी खरीदने समय रखें इन बातों का ध्यान

घर पर टेस्ट के साथ-साथ, घी खरीदते समय आप कुछ सावधानियां भी बरत सकते हैं। इसके लिए घी हमेशा विश्वसनीय और प्रमाणित ब्रांड्स से खरीदें। क्वालिटी सिंबल और सही लेबलिंग की जांच करें।

असामान्य रूप से कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स से बचें। घी की नेचुरल सुगंध और दानेदार बनावट देखें।

आपका बच्चा भी तो नहीं हो रहा स्कूल बुलिंग का शिकार? पेरेंट्स बिल्कुल भी इग्नोर न करें ये 7 संकेत

स्कूल बुलिंग का असर बच्चे की शारीरिक और मानसिक सेहत पर पड़ता है। इसलिए पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वे इस ओर ध्यान दें कि कहीं उनका बच्चा स्कूल में बुली तो नहीं हो रहा।

इस बात का पता लगाने के लिए बच्चों से सही तरीके से बात करना और उन्हें सपोर्ट करना जरूरी है। आइए जानें आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में बुली हो रहा है और इसे रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं।

क्या है स्कूल बुलिंग की डेफिनेशन?

यूनेस्को के मुताबिक, स्कूल बुलिंग एक ऐसी हानिकारक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें ताकत का असंतुलन साफ दिखाई देता है। यह अक्सर दोहराया जाने वाला अवांछनीय व्यवहार है, जो छात्रों या स्कूल कर्मियों के बीच शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक नुकसान पहुंचाता है।

आज के दौर में यह केवल स्कूल के मैदान तक सीमित नहीं है; साइबर बुलिंग के रूप में यह इंटरनेट के जरिए बच्चे तक कहीं भी और कभी भी पहुंच सकती है, जिससे उनकी मानसिक सेहत को गहरा नुकसान पहुंचता है।

बच्चों में बुलिंग के संकेत

कई बार बच्चे अपनी परेशानी बोलकर नहीं बता पाते, लेकिन एक जागरूक पेरेंट होने के तौर पर आपको इन लक्षणों पर गौर करना चाहिए-

शारीरिक संकेत- शरीर पर बिना किसी कारण के चोट, खरोंच या घाव के निशान मिलना।

इमोशनल बदलाव- बच्चा अचानक बहुत ज्यादा अलर्ट, घबराया हुआ या परेशान रहने लगे। गुस्सा आना या चिड़चिड़ा व्यवहार भी एक संकेत हो सकता है।

स्कूल से दूरी- स्कूल जाने या स्कूल के फंक्शन में शामिल होने से डरना, बार-बार सिरदर्द या पेट दर्द का बहाना बनाकर घर वापस बुलाने की जिद करना।

सामाजिक अलगाव- अचानक दोस्तों से मिलना बंद कर देना, सामाजिक स्थितियों से बचना या हमेशा बड़ों के आसपास रहने की कोशिश करना।

नींद और पढ़ाई- ठीक से नींद न आना, डरावने सपने देखना और पढ़ाई के प्रदर्शन में अचानक गिरावट आना।

सामान का नुकसान- कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स या पर्सनल सामान का बार-बार खो जाना या टूट जाना।

ऑनलाइन व्यवहार- फोन या इंटरनेट इस्तेमाल करने के बाद परेशान दिखना या अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज को लेकर बहुत सीक्रेटिव होना।

बुलिंग रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं?

बुलिंग के बारे में बताएं- जब बच्चे समझ जाएंगे कि बुलिंग क्या है, तो वे इसे आसानी से पहचान पाएंगे, चाहे वह उनके साथ हो रही हो या किसी और के साथ।

खुलकर और बार-बार बात करें- अपने बच्चों से रोज बात करें। केवल उनकी पढ़ाई के बारे में ही नहीं, बल्कि उनके अनुभवों और भावनाओं के बारे में भी पूछें। जितना ज्यादा आप उनसे बात करेंगे, वे अपनी समस्याएं शेयर करने में उतने ही कम्फर्टेबल महसूस करेंगे।

आत्मविश्वास बढ़ाएं- बच्चे को उनकी पसंद की एक्टिविटीज या क्लासेज में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि उन्हें एक जैसी हॉबीज वाले दोस्त भी मिलेंगे।

बच्चे को एक पॉजिटिव रोल मॉडल बनाएं- अपने बच्चों को सिखाएं कि दूसरे बच्चों से कैसे व्यवहार करें और बुलिंग के खिलाफ कैसे आवाज उठा सकते हैं।

उनकी ऑनलाइन दुनिया का हिस्सा बनें- बच्चा किन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है, उनसे परिचित हों। उन्हें समझाएं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया आपस में जुड़ी हुई है और उन्हें डिजिटल दुनिया के जोखिमों के बारे में आगाह करें।

खुद उदाहरण बनें- बच्चे अपने माता-पिता को देखकर सीखते हैं। दूसरों को सम्मान दें और जब किसी के साथ गलत हो रहा हो, तो आवाज उठाएं। इंटरनेट पर आपकी पोस्ट और व्यवहार भी उनके लिए एक उदाहरण होता है।

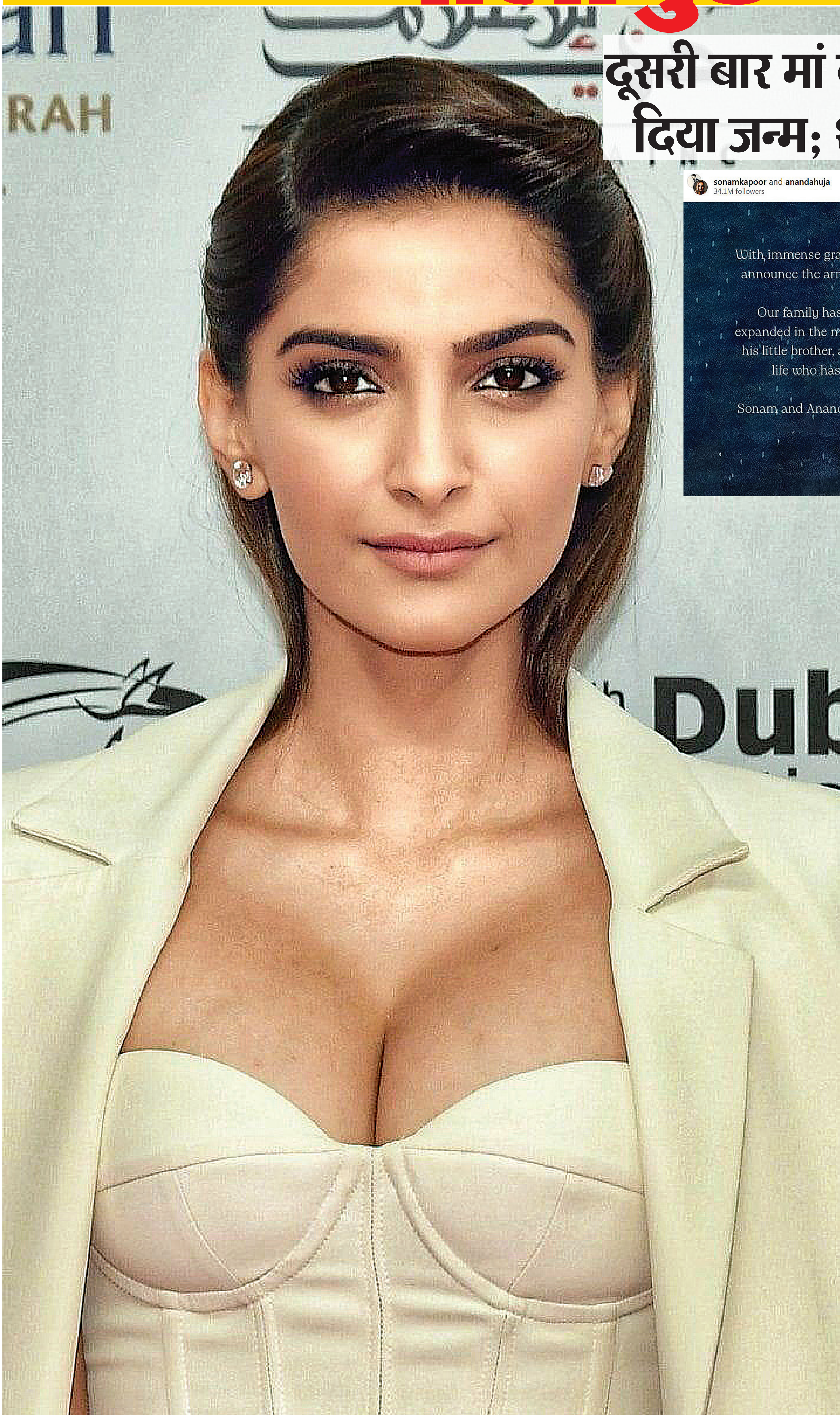

दूसरी बार मां बनीं सोनम; बेटे को दिया जन्म; शेयर की गुड न्यूज

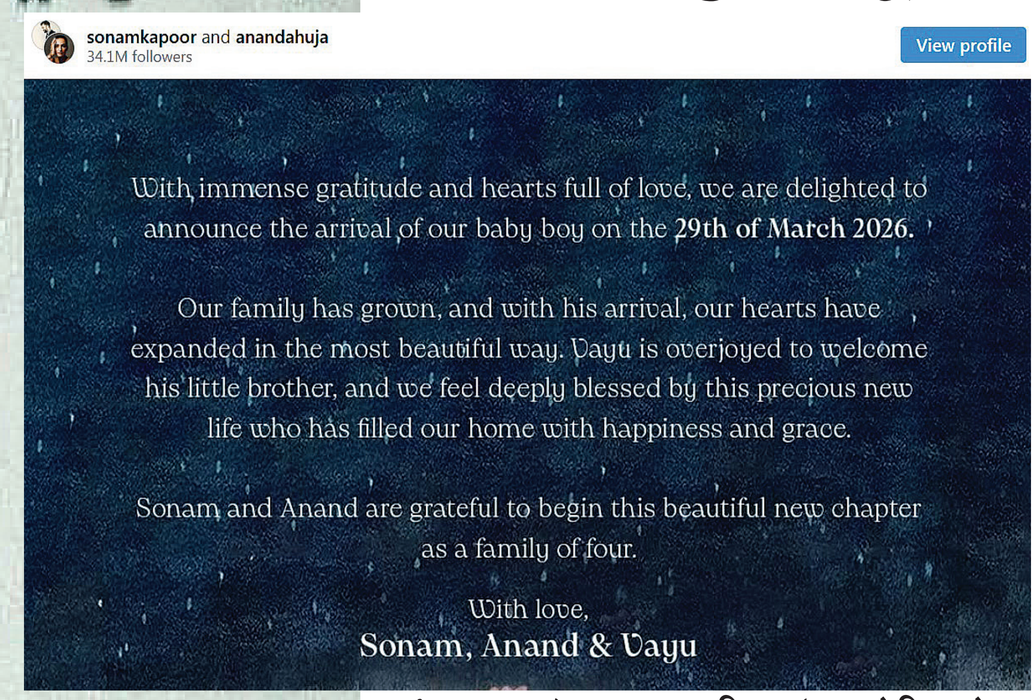

मुंबई। सोनम कपूर और आनंद आहूजा के परिवार में नन्हे मेहमान का आगमन हुआ है। एक्ट्रेस ने रविवार 29 मार्च को दूसरी संतान के रूप में बेटे का स्वागत किया है। बता दें कि कपल के पहले से एक बेटा वायु है।

सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर फैंस के साथ खुशखबरी शेयर की है। साथ ही दुआओं के लिए शुक्रिया कहा है।

सोनम और आनंद ने शेयर किया साझा पोस्ट

सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने आज रविवार को इंस्टाग्राम पर एक साझा पोस्ट शेयर किया है।

इसमें बेटे के जन्म की खबर साझा करते हुए उन्होंने लंबा नोट लिखा है।

कपल ने लिखा है, 'बेहद कृतज्ञता और प्यार से भरे दिलों के साथ हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज 29 मार्च 2026 को हमारे घर एक नन्हे बेटे का आगमन हुआ है'।

लिखा- 'वायु को मिला छोटा भाई'

कपल ने आगे लिखा है, 'हमारा परिवार अब और बड़ा हो गया है। हमारे दूसरे बेटे के जन्म से हमारे दिल भी एक बेहद खूबसूरत तरीके से और विशाल हो गए हैं। वायु अपने छोटे भाई का स्वागत करके बहुत खुश है। हम इस अनमोल नई जान के लिए खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं, जिसने हमारे घर को खुशियों और आशीर्वाद से भर दिया है। हम चार लोगों के परिवार के रूप में इस खूबसूरत नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए ईश्वर के आभारी हैं। सोनम, आनंद और वायु की तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार और शुक्रिया'।

करीना से दीया मिर्जा तक, सेलेब्स ने दी बधाई

सोनम कपूर के घर नन्हे मेहमान के आगमन की खबर पाकर फैंस बधाई दे रहे हैं। साथ ही सेलेब्स ने भी रिएक्शन दिए हैं। सोनम कपूर से लेकर परिणीति चोपड़ा, दीया मिर्जा सहित कई सेलेब्स ने कमेंट कर बधाई दी है।

कमर्शियल LPG सिलेंडर की किल्लत के चलते फेमस यूट्यूबर ने बंद किया रेस्टोरेंट, भाई-भाभी हैं TV के सुपरस्टार

मुंबई। मशहूर टीवी अभिनेता शोएब इब्राहिम की बहन और अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ की ननद, सबा इब्राहिम एक बार फिर चर्चा में हैं। अपनी पर्सनल लाइफ और व्लॉग्स के जरिए दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाली सबा ने हाल ही में अपने रेस्टोरेंट 'खुशामदीद' को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा किया है। सबा ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में खुलासा किया है कि उन्होंने और उनके पति खालिद नियाज ने मिलकर अपने इस रेस्टोरेंट को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। यह खबर उनके प्रशंसकों के लिए काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि 'खुशामदीद' उनके सपनों का प्रोजेक्ट रहा है।

विवादों से रहा है पुराना नाता

सबा इब्राहिम का रेस्टोरेंट पिछले कुछ समय से किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहा है। इससे पहले सबा तब विवादों में घिर गई थीं जब उनके एक व्लॉग की क्लिप वायरल हुई थी। उस वीडियो में उनका परिवार एक व्यस्त हाईवे के किनारे बैठकर रमजान का रोजा इफ्तार करता नजर आया था। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी थी। कई दर्शकों ने सड़क के इतने करीब बैठकर खाना खाने पर चिंता जताई और इसे जोखिम भरा बताया। हालांकि कुछ प्रशंसकों ने उनका समर्थन भी किया, लेकिन इस घटना ने उनके रेस्टोरेंट और व्लॉगिंग स्टाइल पर काफी चर्चा बटोरी थी।

सबा ने अपने व्लॉग में स्पष्ट किया कि रेस्टोरेंट को बंद करने का फैसला रातों-रात नहीं लिया गया, बल्कि इसके पीछे कुछ ठोस तकनीकी और व्यावहारिक कारण हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से रेस्टोरेंट में गैस की भारी किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से किचन का कामकाज सुचारू रूप से चलाना असंभव हो गया था। ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा देने में आ रही इस बाधा के कारण उन्होंने कुछ समय के लिए ब्रेक लेना ही बेहतर समझा। गैस की समस्या के अलावा रेस्टोरेंट के इंटीरियर में भी कुछ खामियां सामने आई हैं। सबा और खालिद ने महसूस किया कि जगह के रख-रखाव और सजावट में सुधार की जरूरत है। उन्होंने तय किया है कि वे इस खाली समय का उपयोग रेस्टोरेंट के रिनोवेशन के लिए करेंगे। उनका मानना है कि एक बेहतर और नए लुक के साथ वापसी करने से ग्राहकों का अनुभव और भी शानदार होगा। एक चलता-फिरता बिजनेस बंद करना कभी भी आसान नहीं होता, और सबा ने भी इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने और उनके पति खालिद ने खुलकर बात की कि इस अस्थायी बंदी से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। एक तरफ जहां बिजनेस रुकने से कमाई बंद हो जाएगी, वहीं दूसरी ओर रिनोवेशन और मरम्मत के काम में उन्हें अपनी जेब से अतिरिक्त पैसा निवेश करना होगा। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद सबा का कहना है कि लंबे समय के फायदे के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य था। वे नहीं चाहती थीं कि आधी-अधूरी सुविधाओं या समस्याओं के साथ वे अपने ग्राहकों की सेवा करें। यह निर्णय उनके पेशेवर रवैये और गुणवत्ता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दिवंगत पिता धर्मेंद्र के फार्महाउस पहुंचीं एशा; गौसेवा करते हुए शेयर किया वीडियो; लिखा- 'यहां शांति मिलती है'

मुंबई। अभिनेत्री एशा देओल हाल ही में गौसेवा करती नजर आईं। उन्होंने गाय और बछड़ों की झलकियां शेयर कीं। एशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से यह वीडियो साझा किया है। एशा ने यह वीडियो अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र के फार्महाउस से साझा किया है। यह वीडियो देख उनके फैंस और यूजर्स कमेंट्स कर रहे हैं।

एशा को पिता के फार्महाउस पर मिलता है सुकून

एशा देओल ने आज सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो साझा किया है। इसमें वे फार्महाउस में मौजूद

गाय और बछड़ों के साथ क्वालिटी वक्त बिताती दिखी हैं। इसके साथ एशा देओल ने कैप्शन लिखा है, 'यह वो जगह है, जहां मुझे सुकून मिलता है'।

बता दें कि अभिनेता धर्मेंद्र अपने सोशल मीडिया अकाउंट से नियमित वीडियो और फोटोज साझा कर अपने फार्महाउस की झलक दिखाते थे।

यूजर्स ने पूछा- 'ममता कुलकर्णी की राह पर हो'?

एशा देओल के इस वीडियो पर नेटिजंस कमेंट्स कर रहे हैं। यूजर्स लिख रहे हैं, 'लगता है यह आपके पिता धर्मेंद्र के फार्महाउस का वीडियो है'। एक यूजर ने लिखा है, 'भगवे वस्त्र... ममता कुलकर्णी की राह पर? ड्रीम गर्ल की 'संन्यासी' फिल्म। इसके अलावा यूजर्स गौमाता की सेवा करने के लिए एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं।

एशा देओल का वर्क फ्रंट

बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और 'ही-मैन' के नाम से मशहूर धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में 24 नवंबर 2025 को मुंबई में निधन हो गया था। एशा देओल, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बड़ी बेटी हैं। एशा देओल के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने 'कोई मेरे दिल से पूछे' से डेब्यू किया था। आखिरी बार एशा को फिल्म 'तुमको मेरी कसम' में देखा गया था। विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित इस फिल्म के जरिए एशा ने लंबे वक्त बाद कमबैक किया।

स्वामी, संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक अश्वनी वर्मा- पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेवार। साई कुंज, नॉर्थ ओक, संजौली, शिमला, हिमाचल प्रदेश- 171006 से प्रकाशित और डीबी कॉर्प लिमिटेड, जीटी रोड, निकट बस स्टैंड सुभानपुर, हमीरा, जिला कपूरथला, पंजाब- 144802 द्वारा मुद्रित।